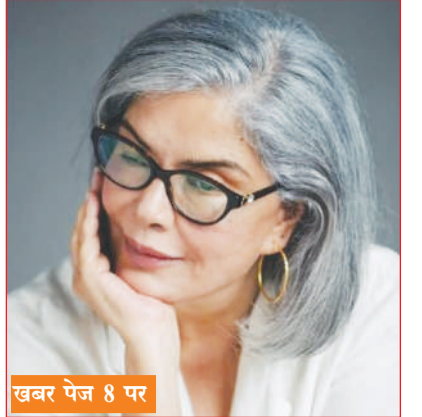




गंभीर समाचार

समय-समाज-संस्कृति



खबर पेज 8 पर

वर्ष -12 अंक-27

प्रांशिक समाचार पत्रिका

कोलकाता, बृहस्पतिवार 16 - 30 अप्रैल 2026

मूल्य: 5 रुपये

RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata

कुल पृष्ठ - 8

सुविचार

- ♦ गमले में रह कर चटवृक्ष नहीं बन सकते अगर बड़ा बनना है तो जमीन में उतरना ही पड़ेगा।
- ♦ गलतियां हर एक इंसान करता है, पर गलती वही स्वीकार करता है, जो गलतियों से सीखता है।
- ♦ हर बार माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं होता है कि कौन सही कौन गलत, कभी कभी माफ़ी मांगने का ये मतलब भी होता है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते...!!
- ♦ एक मित्र ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो - आपको क्या मिलता है ? हमने हंस कर कहा, लेना देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे, वही तो प्यार है,

शेरो-शायरी

- ♦ जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे।
- ♦ इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
- ♦ एक महान शिक्षक बनने के लिए तीन बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जान, जुनून और कल्पना।
- ♦ वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले।

बंगाल में फिर से चलेगा दीदी का 'जादू' या खिलेगा कमल?

एजिट पोल के नतीजों से सुलगी सियासत की आंच

निज संवाददाता : एजिट पोल के नतीजे हमेशा अंतिम परिणाम से मेल खाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। भारत के चुनाव इतिहास में कई बार एजिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। अभी बुधवार को बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। फिर इसी दिन से विभिन्न एजेंसियों के एजिट पोल आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इन सर्वेक्षणों में तस्वीर पूरी तरह एकराफ नहीं है, लेकिन अधिकांश एजेंसियों ने भाजपा को बढ़त में दिखाया है। वहीं कई सर्वे ऐसे भी हैं जो तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में वापसी करते हुए दिखा रहे हैं। आगामी 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब सबकी नजर इसी पर टिकी है। उस दिन यह साफ हो जाएगा कि बंगाल की सत्ता की असली चाबी दीदी के हाथ में आती है या पहली बार कमल का फूल खिलेगा। मैट्रिज के एजिट पोल के अनुसार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को छह से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वाम और कांग्रेस का खाता नहीं खुलने की संभावना जताई गई है।



लगभग सभी एजिट पोल में तृणमूल व बीजेपी के बीच कड़ी और कोटे की टकराव का संकेत मिला है। 294 सीटें वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि भाजपा 77 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार के एजिट पोल मुकाबले को कहीं ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं।

स्टैंडी के सर्वे में भाजपा को 150 से 160 सीटों के साथ बहुमत के पार दिखाया गया है, जबकि तृणमूल को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। पी-मार्क के मुताबिक

भाजपा 150 से 175 सीटें जीत सकती है और तृणमूल 118 से 138 सीटों के बीच रह सकती है। प्रजा पोल ने भाजपा को और भी मजबूत स्थिति में दिखाते हुए 178 से 208

सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि तृणमूल को 85 से 110 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी के सर्वे में भाजपा को 142 से 171 सीटें और तृणमूल को 99 से 127 सीटें

मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ एजेंसियों ने तृणमूल कांग्रेस की वापसी का दावा किया है। पीपल्स पब्लिक के सर्वे में तृणमूल को 178 से 189 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा 95 से 110 सीटों के बीच रह सकती है। जेजीसी के सर्वे में मुकाबला बेहद करीबी बताया गया है, जिसमें तृणमूल को 131 से 152 सीटें और भाजपा को 138 से 159 सीटें मिल सकती हैं। लगभग सभी एजिट पोल में वाम दलों और कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई गई है। अधिकांश सर्वे में इन दलों का खाता तक नहीं खुलने की संभावना जताई गई है या फिर उन्हें 1-3 सीटों तक सीमित बताया गया है। बुधवार को राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 7 जिलों की 142 सीटों पर वोटिंग हुई। इससे पहले 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ था। इस बार राज्य में मतदान प्रतिशत 90 फीसदी के पार पहुंच गया, जो एक रिकार्ड माना जा रहा है।

सबकी निगाहें अब 4 मई पर

बंगाल विधानसभा चुनाव - 2026

पहला चरण - 152 सीटें
मतदान - 23 अप्रैल

दूसरा चरण - 142 सीटें
मतदान - 29 अप्रैल

मतगणना - 294 सीटें
4 मई

Source: ECI

निज संवाददाता : 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान में हुई बंपर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी रिकार्ड तोड़ वोटिंग हुई। 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सर्वाधिक मतदान 91.66 फीसदी दर्ज की गई। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएगी नतीजे सबके सामने आते जाएंगे। वोटों की गिनती 4 मई 2026 को तय है। चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, सीटों के रुझान और नतीजे साफ होते जाएंगे। उम्मीद है कि दोपहर तक सरकार और सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी यह दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगा।

* परिणामों के सबसे तेज और आधिकारिक अपडेट के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट (results.eci.gov.in) पर देख सकते हैं।

* इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव रुझान उपलब्ध होंगे।

* सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनल (टीवी और यूट्यूब) पर नतीजे देख सकते हैं।

चुनावी नतीजों को अपने मोबाइल पर ट्रैक करने के लिए सभी बड़े न्यूज वेबसाइट्स और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडलस पर लगातार अपडेट्स जारी किए जाएंगे। ईसीआई का वोटर हेल्पलाइन ऐप भी रिजल्ट को ट्रैक करने का एक भरोसेमंद डिजिटल माध्यम है।

बेरोज़गारी के साथ-साथ भारत में बढ़ रही है अमीर लोगों की भी संख्या

अंतरराष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

निज संवाददाता : एक तरफ जहां भारत में गरीबी, बेरोज़गारी और वित्तीय असमानता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सुपर रिच (अमीर लोगों) की संख्या भी बढ़ रही है। नाइट फ्रैंक नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था हर साल दुनिया की दौलत पर एक रिपोर्ट निकालती है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के इन्वेंस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और रियल एस्टेट से डील करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें इससे एक दिशा मिलती है। हाल ही में, नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है कि 2026 में दौलत के मामले में दुनिया में कौन कहां खड़ा होगा। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में जो कहा गया है, उससे विवाद खड़ा हो गया है।

इसमें कहा गया है कि भारत में सुपर-रिच (अमीर लोग) लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिनकी दौलत 30 मिलियन से ज्यादा है, वे इस सुपर-रिच ग्रुप में शामिल हैं। नाइट फ्रैंक ने 2026 के लिए अपनी वैश्व रिपोर्ट में कहा कि इस साल भारत में सुपर-रिच लोगों की संख्या बढ़कर 19,877 हो गई है। भारत दुनिया में छठे नंबर पर है। एक तरफ, जहां हम पर कैपिटल इनकम के मामले में 150 से नीचे गिरते जा रहे हैं, वहीं सुपर-रिच के मामले में हम छठे नंबर पर हैं। यह अंतर पहले कभी नहीं देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 और 26 के बीच सुपर-रिच लोगों की संख्या 60 फीसदी बढ़ी है। अगले

5 सालों में यह और बढ़ेगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2031 तक सुपर-रिच लोगों की संख्या बढ़कर 25,217 हो सकती है। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि मौजूदा केंद्र सरकार के राज में यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में सुपर-रिच लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 30 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति वाले लोगों को सुपर-रिच माना जाता है। नाइट फ्रैंक ने 2026 के लिए अपनी वैश्व रिपोर्ट में बताया कि इस साल भारत में सुपर-रिच लोगों की संख्या बढ़कर 19,877 हो गई है। हालांकि, मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में बेरोज़गारी दर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। आजादी के बाद

इतनी बेरोज़गारी पहले कभी नहीं देखी गई। सरकारी और अर्गनाइज्ड क्षेत्र में नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। देश में नौकरियों और रोजगार में कमी गरीबी बढ़ने का संकेत है। जब इस तरह से लोगों का एक ग्रुप अपनी नौकरी खो रहा है और गरीबी की गहराई में डूब रहा है, तो देश की दौलत एक छोट्टे से ग्रुप के हाथों में जमा हो रही है। कुछ लोगों की दौलत को कमी भी देश की कुल दौलत में बढ़ोतरी का इंडिकेटर नहीं माना जाता। देश के सभी लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी ही असली विकास का इंडिकेटर है। लेकिन देश की मौजूदा सरकार उस इंडिकेटर को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं दे रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में भारत वैश्विक औसत से बहुत दूर

डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा

संसद में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का बिल गिरे के साथ ही देश में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से महिलाओं से माफ़ी मांगी है तो दूसरी ओर विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत और सरकार की हार बताया है। हालांकि विपक्ष यह भी कह रहा है कि उनका विश्व सीटों के परिसीमन से अधिक है। खैर यह अलग बहस का विषय हो सकता है। पर एक बात साफ हो जानी चाहिए कि संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं वहीं



भागीदारी की बात करें तो वैश्विक स्तर औसत 27.5 फीसदी है। 30 महिला राष्ट्रपति हैं। 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हालिया चुनावों में 14 राज्यों में महिलाओं की निर्वाचक भूमिका रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 19 राज्यों के शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्वाचक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगातार सभी पार्टियों ने महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव घोषणा पत्र बनाये और

महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की। बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या अन्य प्रदेशों में लक्ष्मिणी देवी या इसी तरह के नाम से मिलती जुलती योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने की रणनीति महिला वोटों को अपनी ओर करने की रही है, यह दूसरी बात है कि इसका लाभ किस पार्टी को अधिक मिला। एक बात साफ हो जानी चाहिए राजनीतिक पार्टियों कहने को कुछ भी कहे या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक महिलाओं की बढ़ नहीं पाई है। महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 फीसदी है वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 फीसदी तक पहुंच पाया है।

एकात्म धाम : बन रहा है एकात्मता का दिव्य केन्द्र

हर्षवर्धन पांडे
भारत की आध्यात्मिक भूमि पर ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक संकल्प एक साथ जुड़कर मानवता को नई दिशा देते हैं। इन्हीं में से एक है एकात्म धाम, जो मध्यप्रदेश के पावन ओंकारेश्वर में स्थित है। यह धाम आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन और एकात्मता के सार्वभौमिक संदेश को समर्पित है। नर्मदा नदी के किनारे मांघाता पर्वत पर स्थित यह स्थल न केवल एक तीर्थ है, बल्कि सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक जागरण और वैश्विक सद्भाव का प्रतीक भी बन रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह ओम आकार का द्वीप प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। किंवदंती है कि विन्ध्य पर्वत ने यहां शिव की आराधना की और शिव स्वयं ओमकारेश्वर रूप में प्रकट हुए। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के जीवन से इस स्थल का गहरा संबंध है। यहीं

गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा पाने के साथ ही उन्होंने अद्वैत दर्शन की गहराई प्राप्त की। शंकराचार्य ने पूरे भारत में चार मठों की स्थापना कर सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया और "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" जैसे महान सिद्धांत दिए। एकात्म धाम इसी योगदान को याद दिलाता है और इन दिनों उनके दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकात्मता के तहत एकात्म धाम का इन दिनों विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अद्वैत वेदांत को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और मानवता में एकत्व का भाव जगाना है। आचार्य शंकर ने भारतवर्ष का भ्रमण कर सम्पूर्ण राष्ट्र को सार्वभौमिक एकात्मता से आलोकित किया। आचार्य शंकर की एकात्मता की प्रतिमा 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बहुधातु से निर्मित है। यह आदि शंकराचार्य को समर्पित है और



एकात्मता का संदेश दे रही है। 21 सितंबर 2023 को इसका अनावरण हुआ था। नर्मदा

मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के तहत एकात्म धाम का इन दिनों विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अद्वैत वेदांत को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और मानवता में एकत्व का भाव जगाना है

नदी और मांघाता पर्वत के सुरम्य वातावरण में यह प्रतिमा दूर से ही दर्शन देती है। यहां स्थित

अद्वैत लोक एक आधुनिक संग्रहालय है, जिसमें आचार्य शंकर के जीवन, उनके दर्शन, शास्त्रार्थ और सनातन धर्म की विभिन्न विधियां, शिल्प और प्रदर्शनियां होंगी। यहां सृष्टि की एकता को समझाने वाले केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान में वेदांत दर्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला पर शोध केंद्र, शंकर कलाग्राम, नर्मदा विहार, ध्यान केंद्र, ग्रंथालय, गुरुकुल और विस्तार केंद्र शामिल हैं। मोहन सरकार द्वारा इसे महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है 2028 तक जिसके मुख्य निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद है। एकात्मधाम के अंतर्गत दूसरे चरण में 2195 करोड़ रुपये की लागत से आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर केंद्रित अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आचार्य शंकर के जीवन, उनके भाष्यों, पांडुलिपियों, दर्शन एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रदर्शित

करना है। परियोजना में संग्रहालय, शोध-केंद्र, शैक्षिक सुविधाएं तथा तीर्थ और सांस्कृतिक पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल करने की रूपरेखा रखी गयी है जिससे न केवल आध्यात्मिक-अध्ययन को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा दौर में जब पूरी दुनिया में भेदभाव, संघर्ष और अलगाव बढ़ रहा है ऐसे में एकात्म धाम यह बताता है कि आत्मता की एकता से ही समाज, राष्ट्र और विश्व की एकता संभव है। मोहन सरकार एकात्म धाम के माध्यम से आचार्य शंकर के दर्शन को वैश्विक फलक पर स्थापित करने के प्रयासों में जुटी हुई है। एकात्म धाम के माध्यम से एमपी सरकार संतों, विद्वानों और आमजन को एक मंच पर लाने का अनुभव कार्य कर रही है जहां युवाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता हो रही है। एमपी की मोहन सरकार के प्रयासों से यह धाम जल्द ही सनातन धर्म की अमर विरासत को संजोते हुए वैश्विक एकता का बड़ा केंद्र बनेगा।

राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के सामने चुनौती

निज संबाददाता : लखनऊ की सियासी गलियों में इन दिनों एक ऐसा विवाद गरमाता जा रहा है जो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को ही चुनौती दे रहा है। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विप्रेष शिशिर द्वारा दायर याचिका अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पहुंच चुकी है, जहां न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने सुनवाई संभाली है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दस्तावेज दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई सात मई तक कर दी है। इससे पहले जस्टिस सुभाष विद्यार्थी इस केस से खुद को अलग कर चुके थे। यह मामला न सिर्फ राहुल गांधी की राजनीतिक छवि पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि भारतीय नागरिकता कानून की पड़ताल भी करा रहा है। भाजपा समर्थक शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा सदस्य बनने की अयोग्यता का आधार बन सकती है। यदि अदालत ने इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाया, तो राहुल की मुश्किलें न सिर्फ कानूनी तौर पर बढ़ेंगी, बल्कि राजनीतिक रूप से भी विपक्ष की एकजुटता पर असर डालेंगी। इस विवाद की शुरुआत लखनऊ की एक निचली अदालत से हुई, जहां शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप था कि राहुल ने 2004-2005 में ब्रिटेन में कंपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। दस्तावेजों के हवाले से शिशिर ने कहा कि राहुल ने बैंकाप

एंटरप्राइजेज (प्रीमियर शिपिंग) कंपनी में डायरेक्टर के रूप में हस्ताक्षर किए, जिसमें नागरिकता ब्रिटिश दर्ज थी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के मुताबिक, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह दोहरी नागरिकता का स्पष्ट मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले से भी प्रतिबंधित है। निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन शिशिर हाईकोर्ट पहुंचे। 17 अप्रैल को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने खुली अदालत में मौखिक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और जांच कराए। यह राहुल के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी नागरिकता पर सवाल उठते, बल्कि लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा। लेकिन अगले ही दिन, 18 अप्रैल को लिखित आदेश में जज ने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को नोटिस जारी किए बिना फैसला उचित नहीं। इस यू-टर्न ने शिशिर को भड़का दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, हालांकि जज का नाम नहीं लिया, लेकिन केस से जुड़े मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां कीं। इससे नाराज जस्टिस विद्यार्थी ने 20 अप्रैल को खुद को केस से अलग कर लिया। अब जस्टिस मनीष माथुर ने कमान संभाली है, और सात मई को नई सुनवाई होगी। शिशिर को दस्तावेज जमा करने का समय मिला है, जिसमें वे ब्रिटिश



सात मई को लखनऊ में सुनवाई

रजिस्ट्रेशन के प्रमाण, राहुल के पिता फीरोज गांधी के ब्रिटिश मूल और परिवार के ऐतिहासिक कनेक्शन के दस्तावेज पेश कर सकते हैं। इस पूरे मामले का राजनीतिक आयाम बेहद रोचक है। भाजपा इसे कांग्रेस के परिवारवाद और विदेशी मूल के पुराने नैरेटिव को फिर से हवा देने का मौका मान रही है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी यही मुद्दा गरमाया था, जब पीएम मोदी ने राहुल कौन हैं का सवाल उठाया था। अब 2024 चुनाव के बाद, जब राहुल नेता विपक्ष बने हैं, यह मुद्दा भाजपा के लिए राजनीतिक हथियार बन सकता है। कर्नाटक से शिशिर का भाजपा से जुड़ाव कोई संयोग नहीं लगता; यह पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर, कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। पार्टी

ब्रिटिश दूतावास या कंपनियों रजिस्ट्रार से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जो समय लेगा लेकिन राहुल को कोर्ट में पेशी देनी पड़ सकती है। दूसरा, यदि कोर्ट राहुल को नोटिस जारी करता है, तो उन्हें हलफनामा देकर नागरिकता साबित करनी होगी। उनके ब्रिटिश पासपोर्ट या कंपनी दस्तावेज नकारना मुश्किल होगा, क्योंकि यूके के रिकॉर्ड सार्वजनिक हैं। तीसरा, शिशिर ने एक और याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है। यदि दोनों याचिकाएं जुड़ जाती हैं, तो मामला और जटिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर यह राष्ट्रीय बहस बन सकता है। इसके कानूनी निहितार्थ गहरे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के तहत, यदि कोई सांसद विदेशी नागरिकता रखता पकड़ा जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना केस में कहा था कि दोहरी नागरिकता अमान्य है। राहुल का मामला इससे मिलता-जुलता है। यदि साबित हो गया, तो उपचुनाव होगा, और कांग्रेस की लोकसभा सीटें घटेंगी। राजनीतिक रूप से, यह 2029 चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करेगा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की मेहनत पर पानी फिर सकता है। लेकिन राहुल के पास मजबूत बचाव है। वे कह सकते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में गलती हुई या यह पुराना मामला है। कांग्रेस ने पहले भी दावा किया कि राहुल जन्मजात भारतीय हैं। विवाद का व्यापक विश्लेषण करें तो यह भारतीय राजनीति की पुरानी बीमारी को उजागर

करता है। नेहरू-गांधी का ठप्पा 1980 से लगा है। इंदिरा गांधी के पति फीरोज के पारसी-ब्रिटिश मूल से लेकर सोनिया गांधी की इतालवी पृष्ठभूमि तक, भाजपा ने इसे हथियार बनाया। अब राहुल पर फोकस है। शिशिर जैसे कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए इसे वायरल कर रहे हैं, जो राहुल ब्रिटिश सिटीजन जैसे ट्रेंड बना सकता है। लेकिन न्यायपालिका पर दबाव न डालें, यही लोकतंत्र की ताकत है। जस्टिस मनीष माथुर का रुख अहम होगा। यदि वे सख्ती बरतते हैं, तो राहुल को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। इससे संसद सत्र बाधित हो सकते हैं, और विपक्ष की आक्रामकता कमजोर पड़ सकती है। एक अन्य कोण यह है कि यह मामला नागरिकता कानून पर बहस छेड़ सकता है। एनआरसी-सीएए विवाद के बाद, अब विपक्षी नेताओं पर ही सवाल उठाना विडम्बना है। शिशिर की याचिका यदि सफल हुई, तो अन्य नेताओं पर भी निशाना साधा जा सकता है। लेकिन फिलहाल, सात मई का इंतजार है। यदि कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, तो राहुल की राजनीतिक यात्रा पर सबसे बड़ा संकट आयातक नागरिकता साबित न कर पाए तो लोकसभा से बाहर। कांग्रेस संगठन में हड़बड़ी मचेगी, और प्रियंका या अन्य चेहरे आगे आ सकते हैं। भाजपा इसे कर्म का फल बताएगी। कुल मिलाकर, यह विवाद न सिर्फ कानूनी जंग है, बल्कि वियासी चालबाजी का खेल भी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक यह चलता रहेगा, और राहुल की किस्मत पर असर डालेगा।

नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के नियमों में दी ढील

मिली बिना लेट फीस के जमा करने की अनुमति

निज संबाददाता : कोलकाता नगर निगम के तहत काम करने वाले सभी व्यापारियों और संस्थानों के लिए एक जरूरी घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रेड लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट (सीई) को रिन्यू और रिन्यू करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक, यह प्रोसेस इस साल 4 अप्रैल से शुरू किया गया है। नगर निगम प्रशासन ने बताया है कि व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय समय में लाइसेंस रिन्यू करने के लिए यह खास पहल है। बिना किसी लेट फीस के लाइसेंस रिन्यू करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 तक की गई है। इस वजह से, अगर व्यापारी इस समय सीमा के अंदर एप्लीकेशन पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त पैसे का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, यह डॉक्यूमेंट शहर के अलग-अलग छोटे, मीडियम और बड़े बिजनेस संस्थानों के लिए जरूरी है। इसे कानूनी तौर पर बिजनेस करने के लिए मुख्य मंजूरीयों में से एक माना जाता है। इसलिए, अगर तय समय में रिन्यू नहीं किया जाता



है, तो भविष्य में जुर्माना या प्रशासनिक दिक्रों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, लोगों की सुविधा के लिए, एप्लीकेशन और रिन्यूअल के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों का मानना है कि इससे नगर निगम में लंबी लाइनों में लगने की जरूरत कम होगी और प्रोसेस जल्दी पूरा हो सकेगा। नगर निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों से तय समय में अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने का अनुरोध किया है। तय समय के बाद एप्लीकेशन जमा करने पर लेट फीस लग सकती है, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त पैसे का बोझ पड़ेगा। इसलिए, सलाह दी जाती है कि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके एप्लीकेशन पूरी कर लें।

सत्राटे में गुम हो रहा है बंगाली लोक कला का गढ़

निज संबाददाता : चितपुर की सड़कों पर ट्राम की घंटियां सुनाई नहीं देतीं, लेकिन उबड़-खाबड़ ट्राम की लाइन अभी भी दिखती है। उस सड़क के किनारे आठ गुणा आठ से लेकर छह गुणा छह या उससे भी छोटी हर तरह की झोपड़ियां हैं। बाहर रंग-बिरंगे पोस्टर लगे हैं। अंदर कोई की जगह फर्नीचर के विज्ञापनों से पटी है। पुराने जमाने की बिना पेंट की हुई लकड़ी या रेडीमेड स्टील की मेजों पर घिसे हुए मोटे कांच के अंदर छिपे वे रंग-बिरंगे चेहरे देखे जा सकते हैं। पोयला बैसाख की इस तपती दोपहर में भी नटी बिनादिनी की यादों से भरे मोहल्ले में वह बात कहां है? कभी इस मोहल्ले को रथ यात्रा, अक्षय तृतीया और बंगाली नववर्ष के पहले शुभ दिन पर भी सांस लेने की फुलत नहीं मिलती होगी। इसे जात्रापाड़ा कहते हैं। बंगाली लोक कला का गढ़। यहां न जाने कितने अभिनेता पैदा हुए हैं? कितनों ने यहां के आधे अंधेरे रिहर्सल रूम को गर्व से अलविदा कहते देखा है कभी उत्तर में टोलीपाड़ा (टालीवुड) यानी बांग्ला सिनेमा का गढ़ को टकरा देने वाले मनोरंजन की इस दुनिया में कौन नहीं आया है। उन्हें देखने के लिए सुदूर गांधी और पंडालों में भीड़ उमड़ती थी। इनमें से कुछ चेहरे जो कभी टॉलीगंज और चितपुर के मोहल्लों में घूमते थे, अब राजनीति की दुनिया में हैं। यह मोहल्ला उनकी कमी महसूस करता है। दिवंगत लोकप्रिय नायक तापस पाल, वर्तमान सांसद शताब्दी राय ने यहां मंच



उत्तर कोलकाता का जात्रापाड़ा प्रेसिडेंट और विधायक उत्तम बारिक भी सोशल जात्रा में स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। विवेक के रोल में उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ होती है। उस जिले के विधायक और मंत्री सोमन महापात्रा ने एक बार एक फिल्म में एक्टिंग की थी। जैसा कि वाममोर्चा के समय में दमकल मंत्री प्रतीम चटर्जी ने किया था। यह बहस अभी भी चल रही है कि क्या टॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स के आने से जात्रापाड़ा की शोहरत बढ़ी है। जात्रापाड़ा के जाने-माने नाम समीर सेन ने कहा-मुझे अपनी तीन जात्रा कंपनियों बंद करनी पड़ी हैं। विश्वभारती, आनंद भारती और कलकत्ता ओपेरा बंद हो गई हैं। असल में, उनमें से कोई भी प्रांफिट नहीं कमा रही है। लेकिन खर्चें बढ़ रहे हैं। दर्शक भी कम हो रहे हैं। कुल मिलाकर, जात्रा, जो पब्लिक एजुकेशन का एक जरिया है, अब बहुत मुश्किल हो गया है। कह सकते हैं बंगाल की इस लोक कला विधा के लिए इसी तरह, पूर्व मेदिनीपुर के

15 साल की नाबालिग की गर्भपात के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बदलने से किया इंकार

निज संबाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग के लगभग 30 सप्ताह के गर्भ के मेडिकल टर्मिनेशन के आदेश में बदलाव से मना कर दिया है। कोर्ट ने 24 अप्रैल को यह आदेश दिया था। 29 अप्रैल को इस बारे में एम्स, दिल्ली की पुनर्विचार याचिका खारिज की थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल क्वैरेटिव याचिका पर भी अपने आदेश को बदलने से मना कर दिया है। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं। उनके साथ ही एम्स के 2 वरिष्ठ डॉक्टर भी कोर्ट में आए। तीनों ने इसे ज़ाह और बढ़ा, दोनों के लिए नुकसानदेह बताया। डॉक्टरों ने कहा कि गर्भ के इतना आगे पहुंच जाने के बाद अब बच्चे को बाहर निकालना सही नहीं है। अब निकाला गया तो बच्चा जीवित रहेगा, लेकिन वह लंबे समय तक या संभवतः जीवन भर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील भी रखी गई कि इस तरह से गर्भपात की कोशिश से यह आशंका है कि लड़की जीवन भर गर्भ धारण न कर सके। इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाम्या बागची की बेंच ने कहा-आप एक परिवार की तरफ से फैसला नहीं ले सकते। आप जो भी कह रहे हैं, वह लड़की और उसके माता-पिता को समझाए। अगर वह सहमत न हों, तो हमारे आदेश का पालन करते हुए मेडिकल प्रक्रिया को पूरा कीजिए। ध्यान रहे कि 24 अप्रैल को मूल आदेश जस्टिस बी वी नागरला और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने दिया था। कोर्ट को बताया गया था कि बच्ची 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए जजों ने कहा था, संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार देता है।

रेयर जेनेटिक बीमारी से पीड़ित देबस्मिता ने सीबीएसई की दसवीं कक्षा में हासिल किए 98.6 प्रतिशत अंक

निज संबाददाता : सोते समय करवट लेने के लिए उसे अपनी मां की मदद की जरूरत पड़ती है। वह पेन का ढक्कन या पानी की बोतल का मुंह नहीं खोल सकती। वह कंपास से गोला नहीं बना सकती। वह शैल्फ से मोटी किताब नीचे नहीं उतार सकती। बावजूद इसके वह जो कर पाई, वह था सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 98.6 परसेंटाइल मार्क्स लाना। देबस्मिता घोष। बांशद्वेनी की रहने वाली देबस्मिता जन्म से ही एक रेयर जेनेटिक बीमारी स्याइनल मस्क्युलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित हैं। व्हीलचेयर पर चलने वाली देबस्मिता ने अंकगणित में 100, बांग्ला में 96, अंग्रेजी में 99, विज्ञान में 97, सोशल साइंस में 97 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 नंबर लाए। इंडस वैली वर्ल्ड स्कूल की स्टूडेंट देबस्मिता अपने स्कूल में भी फर्स्ट आई हैं। देबस्मिता भविष्य में बायो-इंफॉर्मेटिक्स पढ़ना चाहती है। वह अपने सभी अच्छे रिजल्ट्स को अपनी मां, पिता और स्कूल का योगदान मानती है। व्हीलचेयर पर बैठी किशोरी अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियों से अपना गाल दबाते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। यह कोई खास बैठने का तरीका नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके गाल से दो उंगलियां हटती हैं, देबस्मिता की गर्दन अब उसका सिर सीधा नहीं रख पाती। उसका सिर झुक जाता है। तो उसने खुद को इसकी आदत डाल ली है। एसएमए की वजह से देबस्मिता की मांसपेशियों की ताकत खत्म हो रही है। हालांकि व्हीलचेयर पर बैठी किशोरी में अपना सिर सीधा रखने की ताकत नहीं है, लेकिन उसके सीबीएसई 10वीं के नतीजों ने उसके मम्मी-पापा के साथ-साथ उसके स्कूल को भी गर्व महसूस कराया है। स्कूल ने भी अपनी प्यारी स्टूडेंट को बधाई दी है। देबस्मिता के पिता देवाशीष घोष पेशे से बीएसएनएल

मांसपेशियों के क्षरण के कारण हमेशा रहती हैं व्हीलचेयर पर



ऑफिसर हैं और मां मौमिता घोष बंद होना, उसकी फिजिकल कंडीशन ऑटोटेमेटिड हैं। मौमिता ने कहा-उसकी लड़ाई उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन उसे बीमारी का पता चला था। फिजियोथैरेपी, उसे गोद में स्कूल ले जाना-यह हमारी सच्चाई थी। लेकिन

उसने सभी मुश्किलों का सामना किया और अपने डैलेंट और लगन से स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर दिया, और रिजल्ट भी मिले। आज की सफलता यह साबित करती है कि अगर उसे मौका मिलता, तो वह सही जगह होती। यह रिजल्ट उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है जिन्होंने उसे एक दिन मौका नहीं दिया। मुस्कुराते हुए देबस्मिता आगे कहती हैं- मैं इन सब के बारे में नहीं सोचती क्योंकि मेरे दोस्तों की जिंदगी में ये प्रांक्वम नहीं हैं। क्योंकि, मेरे लिए, यह एक नॉर्मल जिंदगी है। मैं इस नॉर्मल जिंदगी से अपने सभी सपने पूरे करने की कोशिश करूंगी। पढ़ाई के अलावा, देबस्मिता को कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वह एक बार में चार से पांच किताबें पढ़ लेती हैं। इस सोलह साल की टिनेजर ने हैरी पाटर से लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी की देवी चौधरी तक सब कुछ पढ़ लिया है। फिर से, देबस्मिता, जिसे प्यार है म्यूजिक, राहुल देव बर्मन और ए. आर. रहमान के गाने पसंद हैं। यह सब उसकी पढ़ाई के बीच होता है। हालांकि, किशोरी का मानना है कि जिंदगी में अनुशासन और नियमितता होना जरूरी है। इसलिए, जब घड़ी में चार बजे, तो उसने बात करना बंद कर दिया। उस समय उसका ध्यान सिर्फ ऑनलाइन क्लास में था। जब वह देबस्मिता के कमरे से निकल रही थी, तो उसकी नज़र उसके लिए रखी कई टूफियों पर पड़ी। जैसे ही वह रुकी, मौमिता ने उसे बताया कि उसकी बेटी को अलग-अलग फ्रील्ड से अवांर्ड मिले हैं-अरियमेटिक ओलंपियाड, अबेकस, चैस-ये सब अवांर्ड। मौमिता रुकी और बोली-उसके इलाज में बहुत खर्चा है। लेकिन क्या इतनी काबिलियत वाली लड़की के लिए रुकना मुमकिन है? टूफियों को देखते हुए बात करना बंद करने वाली मां अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी से झूम रही थी।

किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए धनराशि आवंटित नहीं होने पर बिल स्वीकार नहीं किए जा सकते

निज संबाददाता : अगर किसी खास सेक्टर के लिए फंड आवंटित नहीं किया गया है, तो न तो ट्रेजरी और न ही पीएओ विभाग कोई बिल स्वीकार करेगा। वित्त विभाग की ऑडिट शाखा ने इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। नवात्र की तरफ से जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रशासनिक विभागों और कंट्रोलिंग अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा आवंटित फंड को संबंधित ड्राइंग और वितरण अधिकारी (डीडीओ) को तुरंत उप-आवंटित करना होगा। यह प्रक्रिया आईएफएमएस के ई-वितरण मॉड्यूल के माध्यम से पूरी की जानी है। वित्त विभाग का मानना है कि अगर प्रशासनिक विभाग और कंट्रोलिंग अधिकारी इस उप-आवंटन प्रक्रिया को सिस्टम के माध्यम से समय पर और समझदारी से पूरा करते हैं, तो औपचारिक आवंटन की उम्मीद में फंड निकालने की जरूरत खत्म हो सकती है। हालांकि, दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि विभिन्न मामलों में कुछ छूट लागू होती है, खासकर वेतन और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मामलों में। इसके अलावा, राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों के सालाना स्वास्थ्य जांच के लिए एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। इस मामले में शुरुवार को जारी एक अधिसूचना में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने कहा कि पुरुष

वित्त विभाग के दिशानिर्देश



आईएएस अधिकारियों को 2,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जबकि महिला आईएएस अधिकारियों को 2,200 रुपए मिलेंगे। ये स्वास्थ्य जांच नौ स्वीकृत मेडिकल कालेजों और अस्पतालों, 15 जिला अस्पतालों, या राज्य द्वारा नामित आठ निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में से किसी में भी कराई जा सकती है। इसके अलावा, अगर शुरुआती जांच के बाद चिकित्सीय सलाह के आधार पर कोई अतिरिक्त डायग्नोस्टिक जांच जरूरी समझी जाती है, तो राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 के अनुसार उससे जुड़ी लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

पश्चिम बंगाल में पांच दशक में तीसरी बार हुए 'फ्री एंड फेयर' चुनाव

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल चुनाव में रिगिंग शब्द पहली बार 57 साल पहले विधानसभा चुनाव में चर्चा में आया था। तब से, पश्चिम बंगाल ने कुल 14 विधानसभा चुनाव में देखे हैं। 2011 को मिलाकर, इस राज्य ने 14 चुनावों में से सिर्फ तीसरी बार ही सही मायने में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण वोटिंग देखी है। ऐसे वोटिंग कराने का मुख्य क्रेडिट निश्चित रूप से चुनाव आयोग को जाता है। बिना डरे वोटिंग कराने के लिए पका इरादा रखने वाले आयोग ने यह पका किया है कि दोनों फेज में वोटिंग रेट 90 फीसदी से ज्यादा हो। लेकिन किसी भी चरण में एक भी मौत नहीं हुई है। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आयोग के लिए एक डेटा के मुताबिक, 2026 में पश्चिम बंगाल ने ऐसा असेंबली चुनाव देखा जिसमें कोई मौत नहीं हुई। मतदान वाले किसी भी नहीं, बल्कि कैंप के दौरान भी। लेकिन, पांच साल पहले पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में 24 लोगों की जान चली गई थी। उससे पांच साल पहले 2016 में सात लोग चुनावी हिंसा का शिकार हुए थे। इस बार यह संख्या शून्य है। चुनाव के दिन कहीं भी कोई बम धमाका नहीं हुआ। लेकिन, सिर्फ पांच साल पहले 2021 के चुनाव में 60 से ज्यादा बम धमाके हुए थे। ज्यादातर लोग लगभग बिना खून-खराबे वाला चुनाव कराने का क्रेडिट चुनाव आयोग को देते हैं। उनके मुताबिक,

जिस तरह कमीशन ने एसआईआर प्रोसेस के समय से ही धीरे-धीरे राज्य प्रशासन में अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया, और चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस और प्रशासन में अभूतपूर्व जैसा फेरबदल करके पूरे सिस्टम को बदल दिया, उसी का नतीजा है कि चुनाव आजाद और शांतिपूर्ण तरीके से हुए। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट आयोग के तीन अधिकारियों, सीईओ (चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर) मनोज अग्रवाल और सुब्रत गुप्ता और एक मिश्रा को दिया जा रहा है। मनोज 1990 बैच के आईएस ऑफिसर हैं। नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने राज्य की तरफ से दिए गए तीन पैरल को खारिज करने के बाद मनोज को सीईओ चुना। उनके शांत दिमाग, तेज बुद्धि और सीधे जवाब देने की काबिलियत की खास तौर पर चर्चा होती है। इसी वजह से वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पसंदीदा अधिकारी हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, ज्ञानेश ने चुनाव प्रक्रिया के हर स्टेज पर मनोज की लगभग सभी सिफारिशें मानीं। सुब्रत 1990 बैच के आईएस भी हैं। उनके पास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक की डिग्री है। वे टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर फेज में स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया था। उस प्रोसेस में वोटों की जानकारी और कागजातों को वेरिफाई करने में उनकी



समझदारी काम आई। सुब्रत के काम से खुश होकर आयोग ने उन्हें विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर चार्ज संभाला। सुब्रत ने पुलिस और ऑब्जर्वर के काम पर नजर रखी। आयोग ने रिटायर्ड आईपीएस मिश्रा को स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया। 1988 सिक्किम बैच के ऑफिसर मिश्रा ने लंबे समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटेलेजेंस डिपार्टमेंट में काम किया है। इसीलिए वे कोलकाता आए थे। रिटायरमेंट के बाद वे दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन करीब सात-आठ साल इसी राज्य में रहे। वे पश्चिम बंगाल में काम करना पसंद करते हैं। आयोग के

कई सूत्रों का दावा है कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इन तीनों अधिकारियों का रोल बहुत जरूरी था। उन्होंने ही अशांति से बचने के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाया था। उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पुलिस और प्रशासन को कंट्रोल में लाने की पॉलिसी पर भरोसा करके पश्चिम बंगाल में चुनाव की तस्वीर बदल दी। लेफ्ट का दावा है कि 1972 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के पहले चुनाव थे जब राज्य के लोगों ने धांधली और आतंक देखा। कांग्रेस या तृणमूल नेताओं ने उस थ्योरी को गलत बताया। तृणमूल सांसद सांगत रांय ने कहा-धांधली 1969 से शुरू हुई और यह सीपीएम से शुरू हुई। बाद में, 1971 के विधानसभा चुनाव में

सीपीएम पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कई चश्मदीदों का दावा है कि उस समय के चुनाव (कम से कम वोटिंग) फ्री और फेयर थे। हालांकि, सांगत इसे नहीं मानते। वे कहते हैं-969 की तरह, सीपीएम ने 1971 में भी कई सीटों पर धांधली की। ऐसा करके उसने ज्यादा सीटें जीतीं। अगर खून-खराबा या जान का नुकसान एक पैमाना है, तो 1971 के विधानसभा चुनाव इस साल के चुनावों से पीछे रहेंगे। उस समय राजनीति में अभी भी एक्टिव रहने वाले नेताओं का कहना है कि उस चुनाव में कई लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया था, जो नक्सल युग के आखिर में हुआ था। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि उस चुनाव में

चार कैंडिडेट मारे गए थे। उसके बाद, 1972 में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। सिद्धार्थ शंकर रांय मुख्यमंत्री बने। लेकिन लेफ्ट ने उस चुनाव को राज्य के इतिहास का 'सबसे काला' चुनाव बताया है। सीपीएम अब भी दावा करती है कि ज्योति बसु जैसे कैंडिडेट उस समय के लेफ्ट के गढ़ बरानगर में 'भारी धांधली' की वजह से हारे थे। लेफ्ट का कहना है कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। पुराने कांग्रेसी इस थ्योरी को पूरी तरह मानना नहीं चाहते। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथगत रांय भी लेफ्ट की थ्योरी का पूरी तरह से समर्थन नहीं करते। वे 1972 के धांधली के आरोपों से इनकार नहीं करते। लेकिन तथगत यह नहीं मानते कि 1977 में कांग्रेस इसी वजह से हारी थी। उनके शब्दों में-1977 में, कांग्रेस ने असल में हार मान ली थी। इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा पैदा हुआ था, उससे खुद मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रांय ने हार मान ली थी। उन्होंने उस समय चुनाव नहीं लड़ा। वह लगभग पश्चिम बंगाल से भाग गए थे। कांग्रेस बिखर गई थी। उस खालीपन का फायदा उठाकर, सीपीएम ने खुद को और आगे बढ़ाया। सांगत का फायदा वाला नेताओं का कहना है कि उस चुनाव में कई लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया था, जो नक्सल युग के आखिर में हुआ था। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि उस चुनाव में

को तैयार नहीं हैं। बल्कि, सांगत की तरह, तथगत का मानना है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा स्पॉन्टेनियस था। दो राउंड की वोटिंग के बाद तृणमूल ने इंटरनल एनालिसिस की मांग की, यह 230 के पार होगा। सत्ताधारी पार्टी भवानीपुर, नंदीग्राम सीटों के बारे में क्या सोच रही है? गौरतलब है कि 1977 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय, सांगत बैरकपुर लोकसभा से कांग्रेस कैंडिडेट थे। पूरे राज्य में कांग्रेस कैंप में हो रहे हंगामे के बावजूद सांगत जीते। सीपीएम ने सांगत पर लापरवाही से धांधली का आरोप लगाया था। सांगत इस विवाद से इनकार नहीं कर रहे हैं। उनके शब्दों में-सीपीएम ने शिकायत की थी और इस बारे में मेरे खिलाफ केस भी किया था। लेकिन बाद में सीपीएम ने केस वापस ले लिया। हालांकि, सांगत 2026 के हालिया चुनावों को फ्री और शांतिपूर्ण मानते हैं। उनके खिलाफ जो गुस्सा पैदा हुआ था, उससे खुद मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रांय ने हार मान ली थी। उन्होंने उस समय चुनाव नहीं लड़ा। वह लगभग पश्चिम बंगाल से भाग गए थे। कांग्रेस बिखर गई थी। उस खालीपन का फायदा उठाकर, सीपीएम ने खुद को और आगे बढ़ाया। सांगत का फायदा वाला नेताओं का कहना है कि उस चुनाव में कई लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया था, जो नक्सल युग के आखिर में हुआ था। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि उस चुनाव में

14 मई को आगे उच्च माध्यमिक के नतीजे

निज संवाददाता : राज्य में उच्च माध्यमिक (हायर सेकेंडरी) परीक्षाओं के नतीजे वोटिंग का समय खत्म होते ही घोषित होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की गिनती 4 मई को होगी। उस हफ्ते में नई सरकार बनाने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। फिर इस साल के माध्यमिक के नतीजे आगए। हायर सेकेंडरी परीक्षा के नतीजे अगले हफ्ते घोषित किए जाएंगे। बताया गया है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा के नतीजे 14 मई को घोषित किए जाएंगे। उस दिन सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर, उम्मीदवार वेबसाइट और संबंधित स्कूलों पर नतीजे देख सकेंगे। उन्हें वहां से मार्कशीट मिल जाएगी। 2026 में, हायर सेकेंडरी परीक्षा 12 फरवरी को शुरू हुई थी और 27 तारीख को खत्म हुई थी। नतीजे 14 मई को जारी किए जाएंगे। इस हिसाब से, बोर्ड 78 दिनों के बाद नतीजे



जारी कर रहा है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन पार्थ करमाकर ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि 14 मई को सुबह 10:30 बजे साल्लेक के विद्यासागर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहां से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर स्कूलों को मार्कशीट भेजी जाएगी। कैंडिडेट वहीं से रिजल्ट देख पाएंगे। हालांकि इस साल विधानसभा चुनाव के कारण हायर सेकेंडरी परीक्षा के रिजल्ट जारी होने को लेकर

अनिश्चितता थी। क्योंकि, पहले तो एसआईआर के कारण टीचरों का एक बड़ा हिस्सा लगा था। फिर उन्हें चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया गया। इस वजह से, इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि शिक्षक समय पर परीक्षा रिजल्ट चेक करके जमा कर पाएंगे या नहीं। हालांकि, शिक्षकों ने थोड़ा दबाव बनाकर समय पर रिजल्ट चेक करके जमा कर दिया। इस वजह से समय पर रिजल्ट जारी करना संभव हो पाया।

कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने लोरेटो कॉलेज की ऑटोनामी योजना को ही हरी झंडी

निज संवाददाता : कलकत्ता यूनिवर्सिटी (सीयू) ने कहा है कि लोरेटो कॉलेज ऑटोनामी पाने के अपने प्लान पर आगे बढ़ सकता है। सीयू ने लोरेटो कॉलेज को बताया है कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कॉलेज के ऑटोनामी के लिए यूजीसी में अप्लाई करने के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। यूनिवर्सिटी ने 17 अप्रैल को अपनी सिंडिकेट की बैठक में इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया था। कॉलेज को यूनिवर्सिटी के फैसले के बारे में 20 अप्रैल को बताया गया था। 114 साल पुराने लोरेटो कॉलेज ने जनवरी में ऑटोनामस स्टेटस के लिए यूजीसी में अप्लाई किया था। कॉलेज का इरादा 2026-27 एकेडमिक ईयर से अपनी ऑटोनामस जर्नी शुरू करने का है। ऑटोनामी चाहने वाले कॉलेज के किसी भी एप्लीकेशन के लिए एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को रेगुलेटरी बांडी को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) देना



होगा। लोरेटो कॉलेज की सलाहकार और प्रिंसिपल प्रोफेसर शर्मिला मित्रा ने कहा कि वे औपचारिक नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। मित्रा ने कहा-यूनिवर्सिटी का जवाब यूजीसी को बता दिया गया है। सीयू के वाइस-चांसलर आशुतोष घोष ने कहा- यूनिवर्सिटी के

सिंडिकेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। जैसा कि हमने पहले कहा था, सीयू अपने किसी भी एफिलिएटिंग कॉलेज को ऑटोनामी मांगने पर पूरा सहयोग करेगा। लोरेटो की योजना बीकाम और बीबीए प्रोग्राम, एक लां स्कूल, और सोशल वर्क, एआई, कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म और

कम्युनिकेशन में अंडरग्रेजुएट कोर्स शुरू करने की है। कॉलेज जीआईएस (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर प्रोग्राम भी ऑफर करने का इरादा रखता है। बेहाला कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल शर्मिला मित्रा, जिसे पिछले साल ऑटोनामी मिली थी, ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूजीसी मई तक लोरेटो कॉलेज के एप्लीकेशन पर फैसला ले लेगा। मित्रा ने कहा- अगर लोरेटो कॉलेज को 2026-27 एकेडमिक ईयर से एक ऑटोनामस कॉलेज के तौर पर अपना सफर शुरू करना है, तो कॉलेज को मई तक यह स्टेटस मिल जाना चाहिए। फरवरी में, स्काटिश चर्च कॉलेज ने भी ऑटोनामी के लिए अप्लाई करने का फैसला किया। सीयू के एक अधिकारी ने कहा-कॉलेज ने हमें बताया है कि वह ऑटोनामी के लिए अप्लाई करेगा। हालांकि, उन्हें अभी हमसे एनओसी लेना बाकी है।

कोलकाता नगर निगम ने टैक्स कलेक्शन में कायम की नई मियाल

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच, कोलकाता नगर निगम ने टैक्स कलेक्शन में एक नई मिसाल कायम की है। हाल ही में खत्म हुए 2025-26 वित्तीय वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि कई प्रशासनिक दबावों का सामना करने के बावजूद, राजस्व उगाही में काफी सफलता मिली है। नगर निगम की कुल इनकम 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लगभग 2070 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले काफी बढ़ोतरी है।



हालांकि पिछले साल के मुकाबले नार्थ डिवीजन में थोड़ी गिरावट आई है। नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, यह अतिरिक्त आय भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन, प्रोविडेंट फंड और दूसरी वित्तीय देनदारियों के साथ-साथ विकासमूलक परियोजनाओं को पूरा करने में काफी मददगार होगी। राजस्व में बढ़ोतरी में प्रॉपर्टी टैक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अकेले इसी सेक्टर में करीब 40 करोड़ 60 लाख रुपये ज्यादा जमा हुए हैं। हमेशा की तरह, नगर निगम की ज्यादातर इनकम प्रॉपर्टी टैक्स से ही होती है। हालांकि, इसके अलावा बिल्डिंग फीस, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेड लाइसेंस, एडवर्टाइजमेंट, पार्किंग, एंटरटेनमेंट समेत कुल 13 सेक्टर हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के मामले में शहर को कई डिवीजन में बांटा गया है। इनमें से पिछले फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन साउथ डिवीजन से हुआ था- करीब 551 करोड़ 76 लाख रुपये। दूसरे नंबर पर नार्थ डिवीजन है, जहां कलेक्शन 302 करोड़ 98 लाख रुपये से ज्यादा रहा।

पार किया 2,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा

पूरा नहीं हुआ है। नतीजतन, पोर्टेबिलिटी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बिना हिसाब का रहे गया है। नगर निगम के अनुमान के मुताबिक, अगर इन सभी प्रॉपर्टी को टैक्स के दायरे में लाया जाता है, तो राजस्व उगाही में कम से कम 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भविष्य में और भी कड़े कदम उठाने की योजना है। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा- पिछले कुछ महीनों में, हमें कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ीं। राज्य सरकार के 'हमारा पड़ोस, हमारा समाधान' प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के अलावा, हमें चुनाव आयोग के खास संशोधन के काम में भी शामिल होना पड़ा। इतने सारे दबाव के बावजूद, यह सफलता हमें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कुल मिलाकर, चुनावी माहौल में प्रशासनिक व्यस्तता के बावजूद, जनता का मानना है कि कोलकाता नगर निगम की नई वित्तीय सफलता शहर के अर्बन मैनेजमेंट में एक नई दिशा दिखाती है।

फाल्ता समेत 77 जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत चुनाव आयोग 2 मई से पहले फिर से करवाएगा मतदान

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम फेज की वोटिंग हुई। इस दौरान कई जगहों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की खबरें सामने आईं। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, ईवीएम से छेड़छाड़ के प्रति आयोग ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। ऐसे 77 पोलिंग बूथ को चिह्नित किया गया है, जहां गड़बड़ी हुई है। वोटिंग 2 मई से पहले कराई जाएगी। कोलकाता में मतदान के बीच पत्रकारों से बात करते हुए मनोज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने मशीनरी वेबकास्टिंग, फील्ड रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों के इनपुट सहित कई माध्यमों से घटनाक्रम पर सक्रिय रूप से नजर रखी। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जहां से भी हमें कोई सूचना मिली है, हमने वेबकास्टिंग के जरिए देखा। जहां से फील्ड रिपोर्ट आई हैं, और जब पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आती है, उन मामलों में हम ज़ीरो टॉलरेंस अपनाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने काफी पहले ही अपना खूब साफ कर दिया था कि जहां भी हमें से छेड़छाड़ का कोई भी मामला मिलेगा, वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा।

शहर में बढ़ रहा है हांकरों का अतिक्रमण

चुनाव के बाद कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने शुरू कर दी है मॉनिटरिंग



शहर में हांकरों का कब्जा फिर से बढ़ रहा है। हाल ही में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के हांकर विभाग को ऐसी शिकायत मिली है। आरोप है कि हाकर बेतराम स्ट्रीट, हुमायूं प्लेस और जवाहरलाल नेहरू रोड के ज़रूरी हिस्सों पर भी तेज़ी से कब्जा कर रहे हैं, जिन्हें कोलकाता का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। इसके अलावा, आरोप है कि ओबेरॉय ग्रैंड होटल के सामने पुलिस ने पैदल चलने वालों के लिए जो अलग कारिडोर बनाया था, वह अब धीरे-धीरे हांकरों के कब्जे में जा रहा है। ऐसी सभी शिकायतें मिलने के बाद कोलकाता नगर निगम ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। कोलकाता नगर निगम वोटिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही इस बारे में एक्शन लेना चाहता है। इसलिए, अधिकारी इस बारे में शुरूआती काम पहले ही पूरा कर रहे हैं। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, यह देखा जा रहा है कि शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में हर दिन नए हाकर आकर बस रहे हैं, खासकर खाने-पीने की दुकानों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। नतीजतन, उन इलाके में घूमना-फिरना मुश्किल हो गया है जो असल में पैदल चलने वालों की शिकायत है कि कई

मामलों में उन्हें फुटपाथ छोड़कर सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। कई लोगों का मानना है कि चुनाव के दौरान कोलकाता पुलिस की ठीक से निगरानी न होने की वजह से हालात और मुश्किल हो गए हैं। जो जगहें पहले पार्किंग के लिए खाली कराई गई थीं, उन पर भी हांकरों ने कब्जा कर लिया है। शाम के बाद हालात और खराब हो जाते हैं, जब पार्किंग जोन असल में अस्थाई बाजार में बदल जाते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोलकाता नगर निगम और पुलिस की मिली-जुली पहल से उन इलाकों में बेदखली अभियान चलाया गया था। लेकिन वह अभियान ज्यादा दिन नहीं चला। आरोप है कि बेदखली के बाद हाकर अपनी पुरानी जगहों पर लौट आए हैं और अपना काम-धंधा शुरू कर दिया है। हांकर संगठन के नेता मानते हैं कि हर जगह हांकरों का कब्जा शहर के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि, इस मामले पर कोई भी हाकर नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि, एक वरिष्ठ हांकर नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा-पैदल चलने वालों के लिए बने कारिडोर पर कब्जा करना सही नहीं है। हम हांकरों के अधिकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन सड़कों या ट्रैफिक की जगहों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा-सेंट्रल कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके और उसके आस-पास के इलाकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और टाउन वैंडिंग केमेट्री के नियमों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, मौजूदा चुनाव आचार संहिता के कारण, बड़े बेदखली अभियान फिलहाल रोक दिए गए हैं।

हल करो हीरो बनो का उतर

1. कमलजीत संधू, 2. बछेन्द्र पाल, 3. मई 1972,
4. टचस्क्रिन, 5. शून्य-आधारित बजट, 6. 1930,

संपादकीय

कई मायनों में कुछ हटके रहा बंगाल विधानसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब 4 मई को नतीजों का इंतजार है। एक तरफ जहां, मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, वहीं, दूसरी तरफ, विपक्षी बीजेपी ने भी चुनाव फतह करने के लिए सारे संसाधन लगा दिए। बड़ी बात यह कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव कम से कम दो मामलों में अलग रहे हैं जो अपने-अपने तरीके से ज़रूरी हैं। पहला पहलू है ज़्यादा वोटिंग रेट। बुधवार को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान 91 फीसदी से ज़्यादा वोटिंग हुई; इससे पहले, पहले चरण में भी मतदाताओं ने ज़बरदस्त रिव्सांस देखा था। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने, ज़ाहिर है, अपने-अपने तरीके निकाले हैं। 4 मई को मतगणना के दिन इनकी परीक्षा होगी। दूसरा, उतना ही ज़रूरी, फ़र्क चुनावी हिंसा में साफ़ कमी से जुड़ा है। यह एक ऐसी बीमारी है जो इस राज्य के चुनावों की एक खासियत रही है। आर्म्ड कॉन्फ़्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट (सशस्त्र संघर्ष स्थान और घटना डेटा परियोजना), जो झगड़े पर नज़र रखने वाली एक संस्था है, के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 के विधानसभा चुनाव बंगाल के सबसे ख़ूनी थे, जिसमें हिंसा की 300 घटनाएँ हुईं और करीब 60 मौतें हुईं। छिट-पुट घटनाओं को छोड़कर, इस बार ऐसी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। इसका कारण बड़े पैमाने पर सुरक्षा बंदोबस्त हो सकता है। चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 2,300 से ज़्यादा कंपनियाँ तैनात की थीं, जबकि पहली बार केमरा वाले ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए थे। अब चुनौती यह पक्का करना होगी कि बंगाल में एक और ध्रुवीकरण चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद खून-खराबा न हो। लेकिन चुनाव सुरक्षा राजनीतिक ज़रूरतों से भी मुक्त होनी चाहिए। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि रात में हथियारबंद केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान उनसे मिलने आए थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव के दिन विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो उन्हें नतीजे भुगतने होंगे। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय बल ने डराने-धमकाने का काम किया। विपक्ष के पास भी बेशक अपनी शिकायतों की लिस्ट होगी। ऐसे आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए और तय प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि न सिर्फ़ प्रतियोगी बल्कि चुनाव के संस्थागत पर्यवेक्षक भी बिना किसी भेदभाव के काम करें। चुनावी सुरक्षा बनाए रखने के नाम पर कोई भी एक लेवल चुनावी मैदान पर कब्ज़ा नहीं कर सकता।

जानें अपना राशिफल

- मेष**
शुभ समय हो सकता है, कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है, किसी नये व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है जो फायदेमंद होगा, परिवार के लोग पूरा साथ दे सकते हैं।
- वृषभ**
अद्भुत समय हो सकता है इसलिए सिर्फ़ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, अपने परिवार को प्रसन्न रखें, मन स्थिर रखें।
- मिथुन**
विचलित रहने वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ़ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी के चक्कर में आने से बचना काम बिगड़ सकता है सावधान रहे, मन शान्त रखें।
- कर्क**
राहत भरा समय हो सकता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करें, आपसी प्रेम बनाये रखें।
- सिंह**
अभिमान वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सोच समझकर ही करें, कोई रुका हुआ सरकारी काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करें, आपसी सहमति बनाये रखें, मन स्थिर रखें।
- कन्या**
जोखिम वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सावधान रहकर ही करें, रोकड़ी रुपये लेनदेन करने से बचने की आवश्यकता है, अपने परिवार को प्रसन्न रखें, मन वश में रखें।
- तुला**
त्याग करने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करें, अपनी बुद्धिमानी दिखाने की ज़रूरत है, मन स्थिर रखें।
- वृश्चिक**
खर्चीला समय हो सकता है इसलिए सावधान रहकर काम करने की आवश्यकता है, ज़्यादा खर्च परेशानी का कारण बन सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, मन शान्त रखें।
- धनु**
शानदार समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, कोई वाहन खरीदने का विचार हो सकता है, मन में उत्साह रहेगा।
- मकर**
मन परसंद समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है, कोई वाहन खरीदने का विचार हो सकता है, आपसी प्रेम बनाये रखें, मन प्रसन्न रहेगा।
- कुंभ**
प्रतिशोध वाला समय हो सकता है कोई सिर्फ़ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने से झगड़ा भी हो सकता है, बिना काम बाहर नहीं जाये, मन वश में रखें।
- मीन**
कीर्तिमान बनाने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है प्रयास करें, किसी विदेश में व्यापार करने पर विचार हो सकता है जो फायदेमंद होगा, मन प्रसन्न रहेगा।

डिजिटल दौर में बदलती हिंदी पत्रकारिता: स्याही से पिकसल और अब एआई तक का सफर

अजय कुमार
हिंदी पत्रकारिता का इतिहास गवाह है कि इसने हमेशा समाज की धड़कनों को शब्दों के जरिए कागज़ पर उतारा है, लेकिन पिछले एक दशक में इस सफर ने जो मोड़ लिया है, वह किसी महाकाव्य के अध्याय बदलने जैसा है। कल तक सुबह के अखबार की दस्तक और चाय की चुस्की के साथ शुरू होने वाला सूचनाओं का सिलसिला अब अंगूठे के एक स्वाइप पर सिमट गया है। प्रिंट मीडिया, जो कभी सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा करने का इकलौता जरिया था, आज डिजिटल और वीडियो प्लेटफॉर्म की सुनामी के बीच अपनी जमीन बचाने और खुद को नए सांचे में ढालने की जद्दोजहद कर रहा है। यह बदलाव केवल तकनीक का नहीं है, बल्कि यह पत्रकारिता के मिजाज, उसकी भाषा और सबसे महत्वपूर्ण, उसके सरोकारों के बदलने की कहानी है। जब हम प्रिंट से डिजिटल और फिर यूट्यूब के इस त्रिकोणीय सफर को देखते हैं, तो आंकड़ों की जुबानी इस बदलाव की भयावहता और भय्यता दोनों समझ आती है। एक दौर था जब हिंदी के प्रमुख अखबारों की प्रसार संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, लेकिन हालिया वर्षों में डिजिटल फ़र्स्ट के मंत्र ने इस समीकरण को उलट दिया है। आज भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 80 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा अपनी खबरों के लिए केवल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर निर्भर है। प्रिंट के दौर में डेडलाइन का एक अनुशासन था। संपादक के पास समय होता था कि वह खबर की तह तक जाए, उसे परखे और



हिंदी पत्रकारिता का यह सफर स्याही से पिकसल और अब एआई तक तो पहुंच गया है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी बनी रहेगी जब यह सत्य की उस मशाल को जलाए रखेगा जिसे लेकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पुरोधायों ने इसे शुरू किया था। तकनीक और मशीनें केवल उपकरण हो सकती हैं, पत्रकारिता की आत्मा तो हमेशा मानवीय विवेक और जनसरोकार ही रहेगी।

फिर पाठकों के सामने परोसे। लेकिन आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और वायरल कल्चर ने उस ठहराव को छीन लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खबर की रफ़्तार को तो पंख लगा दिए, लेकिन इस रफ़्तार में कहीं न कहीं वह गहराई पीछे छूट गई जो कभी हिंदी लेखनी की पहचान हुआ करती थी। इस संक्रमण काल में सबसे अधिक प्रभावित हुई है पत्रकारिता की भाषा और उसका अर्थशास्त्र। जो हिंदी कभी साहित्यिक मर्यादाओं और व्याकरण की शुचिता से बंधी थी, वह अब क्लिक पाने की मजबूरी में हिलिश और बोलचाल की सरलता की ओर झुक गई है। डिजिटल स्क्रीन पर पाठक की एकाग्रता का समय (अटेंशन स्पैन) मात्र 8 से 12 सेकंड रह गया है, इसलिए अब लंबे विश्लेषणों की जगह इनफ़ोफ़्रॉफ़िक्स और शॉर्ट्स ने ले ली है। यूट्यूब जैसे मंचों ने तो पत्रकारिता के व्याकरण को ही उलट दिया है। यहां अब एकर और संवाददाता के बीच की

लकीर मिट गई है। हर वह व्यक्ति जिसके पास कैमरा और इंटरनेट है, वह खुद को एक मीडिया संस्थान के रूप में पेश कर रहा है। इससे एक ओर तो मुख्यधारा के मीडिया से छूटे हुए मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन दूसरी ओर सतही ज्ञान और सनसनी का एक ऐसा बाजार सज गया है जिसने गंभीर विमर्श को हाशिए पर धकेल दिया है। अब इस परिदृश्य में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रवेश एक नए और चुनौतीपूर्ण युग की आहट है। न्यूज़हॉल के भीतर अब एआई केवल डेटा विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खबरों को लिखने, अनुवाद करने और यहां तक कि न्यूज़ एंकरिंग तक में दखल दे रहा है। एआई ने पत्रकारिता की कार्यक्षमता को तो कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसने मानवीय संवेदना और नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक मशीन खबर लिखती है, तो वह तथ्यों को जोड़ तो सकती है,

लेकिन वह उस मानवीय पीड़ा को शब्द नहीं दे सकती जो एक रिपोर्टर मीके पर महसूस करता है। एआई का सबसे खतरनाक प्रभाव डीपफेक के रूप में सामने आ रहा है, जहां 70 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता असली और नकली वीडियो में फर्क नहीं कर पाते। एल्गोरिदम अब यह तय कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ेंगे, जिससे समाज में फिल्टर बबल बन रहे हैं यानी व्यक्ति केवल अपनी पसंद की कट्टर सोच वाली खबरों ही देख पाता है। आर्थिक मोर्चे पर भी यह बदलाव किसी भूकंप से कम नहीं है। प्रिंट मीडिया का जो विज्ञापन राजस्व कभी 40 प्रतिशत की दर से बढ़ता था, वह अब सिमटकर डिजिटल दिग्गजों की जेब में जा रहा है। डिजिटल मीडिया में राजस्व का मांडल अभी भी प्रयोग के दौर से गुजर रहा है। पेवॉल और सब्सक्रिप्शन जैसे कोशिशें हिंदी पट्टी में अभी भी संघर्ष कर रही हैं। नतीजा यह है कि राजस्व के लिए मीडिया घरानों को अब स्पॉन्सर्ड कंटेंट

का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे निष्पक्षता की दीवारें कमजोर हुई हैं। यूट्यूब ने एक नए अर्थशास्त्र को जन्म दिया है, जहां व्यूज़ और वॉच टाइम ही सबसे बड़ी मुद्रा है। जब खबर का महत्व उसकी सामाजिक उपयोगिता से नहीं बल्कि उसके वायरल होने की क्षमता से तय होने लगे, तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए खतरे की घंटी है। बावजूद इसके, इस बदलाव ने पत्रकारिता को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के वातानुकूलित कमरों से निकालकर छोटे शहरों और कस्बों की गलियों तक पहुंचा दिया है। आज ग्रांड रिपोर्टिंग का अर्थ केवल बड़े चैनलों की ओबी वैन नहीं, बल्कि एक मोबाइल हाथ में थामे वह निर्भीक पत्रकार भी है जो सत्ता से सीधे सवाल पूछ रहा है। भविष्य की हिंदी पत्रकारिता अब एक हाइब्रिड मांडल की ओर बढ़ रही है। अखबार अब केवल सूचना के वाहक नहीं, बल्कि गहन विश्लेषण के दस्तावेज़ बन रहे हैं। एआई के दौर में असली चुनौती केवल तकनीक को अपनाने की नहीं है, बल्कि उस साख को बचाने की है जो मशीनी शोर में कहीं दब गई है। हिंदी पत्रकारिता का यह सफर स्याही से पिकसल और अब एआई तक तो पहुंच गया है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी बनी रहेगी जब यह सत्य की उस मशाल को जलाए रखेगा जिसे लेकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पुरोधायों ने इसे शुरू किया था। तकनीक और मशीनें केवल उपकरण हो सकती हैं, पत्रकारिता की आत्मा तो हमेशा मानवीय विवेक और जनसरोकार ही रहेगी।

शहर के नज़दीक बने एक फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वो दोनों बिलकुल एक जैसे दिखते थे, पर पास जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहां से निकाला नहीं था बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा और आराम के साथ रखा था। अगर कोई घोड़ा और ध्यान देता तो उसे ये भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता और उसके पीछे-पीछे बाड़े में



घूमता। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता, वह बीच-बीच में पीछे मुड़कर देखा और इस

वापस अपने स्थान पर पहुंच जाए, और उसके बाद ही वो अपनी जगह की ओर बढ़ता। दोस्तों, बाड़े के मालिक की तरह ही भगवान हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते कि हमारे अन्दर कोई दोष या कमियां हैं। वो हमारा ज्वाल रखते हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है तो किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। कभी-कभी हम वो अंधे घोड़े होते हैं, जो भगवान द्वारा बांधी गयी घंटी की मदद से अपनी परेशानियों से पार पाते हैं तो कभी हम अपने गले में बांधी घंटी द्वारा दूसरों को रास्ता दिखाने के काम आते हैं।

एक बार एक आदमी को अपने बगिचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज़ वो आदमी उसे देखने लगा, और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटो उसे देखता रहा। उसने देखा की तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पायी, और फिर वो बिलकुल शांत हो गयी मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए



उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठायी और कोकून की छेद को इतना बड़ा कर दिया की वो तितली आसानी से बाहर निकल सके और यही हुआ, तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था, और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोच कर देखा रहा कि वो किसी भी वक़्त अपने पंख फैला कर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी

की जिन्दगी इधर-उधर घिसटते हुए बीतानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया की दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी-कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी मेहनत के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अंपंग के सामान हो जायेंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिये वो आपको कुछ ऐसा सीखा जायेंगे जो आपकी जिन्दगी की उड़ान को आसान बना पायेंगे।

हल करो हीरो बनो

- एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ?
(क)कमलजीत संधू (ख) सुचेता कृपलानी (ग)राजिया बेगम (घ)बछेंद्री पाल
- माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ?
(क)कल्पना चावला (ख)रजिया सुल्तान (ग)बछेंद्री पाल (घ)सुचेता कृपलानी
- राजाराम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब प्रकाशित हुआ।
(क) मई 1972 (ख) जून 1972 (ग) जुलाई 1972 (घ) अगस्त 1972
- निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है।
(क) मॉनिटर (ख) टचस्क्रीन (ग) प्रिंटर (घ) प्लॉटर
- पिछले वर्ष के बजट पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट तैयार करना क्या कहलाता है।
(क) योजना बजट (ख) विस्तृत बजट (ग)निष्पादन बजट (घ)शून्य-आधारित बजट
- डॉ. रंगनाथन द्वारा निर्मित 'मांडल लाइब्रेरी एक्ट' को अखिल एशिया शिक्षा कॉन्फ़ेस में कब प्रस्तुत किया गया।
(क) 1930 (ख) 1931 (ग) 1932 (घ) 1933

उत्तर इसी अंक में खोजें

माथापच्ची-25

	5	9	4	6
			1	3
3	4		6	7
5	9	4		
2		3		8
				1
6			7	8
	1		4	8
		5	3	7

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3X3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। उत्तर अगले अंक में

मार लो मुस्क़ी

बीबी: वैकसीन लगवा आए? सुदामा से भी गरीब होते है !!
पति: हां?
बीबी: दर्द हो रहा है क्या?
पति: कुछ खास नहीं...
बीबी: दूसरी ओरत सुई लगाए तो दर्द नहीं होता और हमारी तो बातें भी चुभ जाती हैं।
पति-पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ। पति दुखी होकर एक सल्लंग में चला गया। वापस आया तो पत्नी ने पूछा- कहां गए थे?
पति बोला- प्रचन सुनने। पत्नी बोली कुछ असर पड़ा या नहीं?
पति-कुछ नहीं बोला और अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया।
पत्नी शरमाते हुए बोली- क्या प्रचन में रोमांस करने के लिए कहा है?
पति-(लंबी सांस छोड़ते हुए) नहीं, महात्मा जी का कहना है कि अपने दुःख खुद उठाओ।
एक शराबी आकाश में देखकर दूसरे शराबी से पूछने लगा ये चांद है या सूरज।
दूसरा शराबी: पत्ता नहीं मैं तो इस शहर में नया हूं।
टीचर- बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होती है।
छात्र- रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं, सफुर होते...
कुछ दोस्त बड़े अजीब होते है, फिर भी दिल के करीब होते है, ना करते ये फोन, ना ही करते ये भेसेज, क्योंकि ये हारामी

माथापच्ची 24 का हल

3	4	1	5	8	2	7	6	9
5	8	6	9	7	1	4	2	3
2	7	9	4	3	6	8	1	5
7	2	3	1	9	5	6	8	4
1	6	8	3	2	4	5	9	7
4	9	5	8	6	7	1	3	2
8	1	2	7	5	9	3	4	6
9	3	7	6	4	8	2	5	1
6	5	4	2	1	3	9	7	8

सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मायावती की सत्ता में वापसी की तैयारी

संजय सक्सेना
उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के नारे के साथ मिशन-2027 का बिगुल फूंक चुके हैं और सत्तारूढ़ भाजपा सत्ता की हैटिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी ताकत शोक रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी खामोश लेकिन बेहद मारक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पिछले कुछ समय से दो ध्रुवीय होती दिख रही थी, उसे मायावती एक बार फिर त्रिकोणीय बनाने की कवायद में जुट गई हैं। इस बार उनकी रणनीति सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जमीनी स्तर पर डेटा और सोशल इंजीनियरिंग के घातक मिश्रण के साथ मैदान में उतर रही हैं। मायावती के लिए यह चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने और दलित राजनीति की धुरी को फिर से अपने पाले में लाने की बड़ी चुनौती है। मायावती ने इस बार अपने पते बेहद सावधानी से खोले हैं। उन्होंने 2027 के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में एक नया और तकनीकी

मोड़ दिया है, जिसे एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) अभियान से जोड़ा गया है। आम तौर पर पार्टीयां चुनाव से ऐन पहले टिकट बांटती हैं, लेकिन बसपा ने पहले ही करीब 40-50 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि, अब इस रणनीति में अचानक बदलाव किया गया है। मायावती ने अब उन नेताओं को तबजो देने का फैसला किया है जिन्होंने एसआईआर अभियान के अचानक बदलाव से सख्त विरोध किया है। पार्टी का मानना है कि चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि वोट लिस्ट में अपने समर्थकों के नाम सुरक्षित रखने से जीते जाते हैं। मायावती ने करीब 15 हजार बूथ कमेटीयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट का मकसद यह समझना है कि कहां उनके वोट बैंक में संघर्ष लगी है और कहां साजिश के तहत समर्थकों के नाम काटे गए। जो पदाधिकारी इन कटे हुए नामों को दोबारा जुड़वाने और बूथ को मजबूत करने के मोर्चे पर सफल रहे हैं, उन्हीं की दावेदारी अब टिकट के लिए पुख्ता मानी जाएगी। बसपा की इस नई रणनीति के केंद्र में वह सोशल इंजीनियरिंग है, जिसने 2007 में पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंचाया था। मायावती एक बार फिर दलित-



मिशन 2027

ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ को जीवित करने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी समीकरणों के बीच मायावती यह समझ चुकी हैं कि केवल एक वर्ग के भरोसे सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए उन्होंने हर विधानसभा सीट पर चार-चार दावेदारों का पैक तैयार करवाया है। इन दावेदारों को उनकी जातीय पकड़ और स्थानीय समीकरणों के आधार पर परखा जा रहा है। मायावती ने मंडल और जोनल कोऑर्डिनेटों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे जातियों के गणित की सटीक रिपोर्ट दें। अगर

किसी सीट पर दलित वोटों के साथ मुस्लिम या ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, तो वहां उसी समाज के मजबूत चेहरे को तलाशा जा रहा है। यह प्रक्रिया काफी गहरी है, जिसमें पहले क्षेत्र प्रभारी बनाया जाता है और फिर उसकी सक्रियता के आधार पर उसे प्रत्याशी घोषित किया जाता है। मायावती का दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली का दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां बसपा का आधार हमेशा से मजबूत रहा है, वहां के समीकरणों को दुरुस्त करने की

जिम्मेदारी मायावती ने खुद संभाली है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि पार्टी इस बार किसी बड़े दल से गठबंधन के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मानना है कि गठबंधन से उनके वोट दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों के वोट बसपा को नहीं मिलते। ऐसे में अपने पारंपरिक वोट बैंक को सहेजकर रखना और उसमें दूसरे वर्गों को जोड़ना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। मायावती अब उन बूथों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जहां पिछले चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निरा था। वह खुद जिलों से आने वाली एक-एक रिपोर्ट की समीक्षा कर रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं, उन्हें दोबारा हर हाल में जुड़वाया जाए। इस पूरे अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह संदेश है जो मायावती अपने कार्यकर्ताओं को दे रही हैं। वह लगातार बैठकों में इस बात का जिक्र कर रही हैं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच खुद कर रही तकरार के बीच मायावती खुद को एक गंभीर और अनुशासित विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं। वह जानती हैं कि

2027 में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उन छोटी जातियों और समुदायों से होकर गुजरता है जो फिलहाल मुख्यधारा की राजनीति में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके टिकट बितरण में इस बार जातियों की केमिस्ट्री पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एसआईआर अभियान से हुए नफे-नुकसान का आकलन कर उम्मीदवारों के चयन की यह पद्धति उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग है, जो यह दर्शाता है कि मायावती अब पुरानी शैली को आधुनिक चुनावी प्रबंधन के साथ जोड़ रही हैं। हालांकि, राह इतनी आसान भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के लिए भाजपा और सपा दोनों ने ही बड़ी संघमारी की है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नए युवा चेहरों ने भी दलित राजनीति में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में मायावती का पुराना सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला कितना कारगर होगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन मायावती का इतिहास रहा है कि वह जब भी खामोश होती हैं, तो किसी बड़े सियासी धमाके की तैयारी में होती हैं। उनके पास अपना एक समर्पित कैंडिडेट है जो आज भी उनके एक इशारे पर लामबंद हो जाता है। 2007 के करिश्मे को 2027 में दोहराने के लिए उन्होंने संगठन के

ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ब्राह्मण और मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर मैदान में उतारने की तैयारी यह संकेत देती है कि बसपा इस बार किसी भी हाल में चुनावी मुकाबले को दोतरफा नहीं होने देगी। बहरहाल, 2027 का चुनाव बसपा के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। मायावती की यह सूक्ष्म रणनीति, जिसमें बूथ लेवल की रिपोर्टिंग से लेकर जातीय समीकरणों का जटिल जाल बुना गया है, इ विपक्षी खेमों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। क्या मायावती फिर से वही पुराना जादू चला पाएंगी? क्या एसआईआर अभियान के जरिए तैयारी की गई उम्मीदवारों की नई फौज बसपा की नैया पार लगा पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय की रैलियों और चुनावी माहौल में मिलेगा। फिलहाल तो हाथी अपनी मद्दमस्त चाल से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दिख रहा है, और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग एक बार फिर यूपी की सियासत का सबसे चर्चित अध्याय बनने की ओर अग्रसर है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसका एक ही लक्ष्य है सत्ता के शिखर पर बसपा का दोबारा परचम लहराना।

आईसीएसई ने द्वितीय भाषा के पाठ्यक्रम को बांटा

निज संवाददाता : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एजामिनेशन (आईसीएसई) ने बांग्ला, हिंदी और कुछ दूसरी भाषाओं के लिए सेकंड-लेवेल सिलेबस (द्वितीय भाषा के पाठ्यक्रम) को कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12 के बीच बांटने का फैसला किया है। इस सिस्टम के तहत, आईसीएसई (क्लास 10) के स्टूडेंट्स का टेस्ट सिर्फ क्लास 10 के लिए तय सिलेबस के हिस्से पर होगा, क्लास 9 के हिस्से पर नहीं। इसी तरह, आईएससी (क्लास 12) के स्टूडेंट्स का टेस्ट सिर्फ क्लास 12 के सिलेबस के हिस्से पर होगा, क्लास 11 के हिस्से पर नहीं। क्लास 9 और 11 के एजाम उन खास क्लास के लिए तय सिलेबस के आधार पर संबंधित स्कूल आयोजित करेंगे। काउंसिल ने क्लास 9 और 10 और क्लास 11 और 12 के लिए तय टेस्ट को हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, ओडिया, उर्दू, नेपाली और भूटिया में बांट दिया है। काउंसिल ने कहा है कि आईसीएसई में असमिया और मराठी का सिलेबस भी बांटा जाएगा। इस हफ्ते स्कूल प्रमुख को भेजे गए एक सर्कुलर में काउंसिल ने कहा-सभी स्टूडेंट्स के लिए भाषा सीखना



कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 के लिए अलग-अलग निर्धारित पाठ होंगे

मांड्यूलर, दिलचस्प और काम का बनाने के लिए, सीआईएससीई परीक्षा वर्ष 2027 से चुनी हुई भारतीय भाषाओं के लिए तय टेस्ट की पढ़ाई को बांट रहा है। तय टेस्ट का ऐसा ही बंटवारा परीक्षा वर्ष 2028 में भी किया जाएगा। हालांकि, काउंसिल ने कहा है कि यह बंटवारा सिर्फ तय टेस्ट पर लागू होगा, भाषा वाले हिस्से पर नहीं। काउंसिल प्रमुख ने कहा कि इस बंटवारे से बोर्ड के एजाम देने वालों पर दूसरी भाषा का बोझ कम होगा और ज्यादा एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग के लिए जगह बनेगी।

सीआईएससीई के चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी जोसेफ इमैनुएल ने बताया-इससे ज्यादा बोझ कम होगा। यह सिर्फ एकेडमिक पहलू नहीं है, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग है जो एक स्टूडेंट को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह (बांटना) एकेडमिक प्रेशर कम करेगा और भाषा सीखने को बढ़ावा देगा। भारतीय भाषाओं में बंटवारा दूसरे सबजेक्ट्स और इंग्लिश में भी बराबरी लाएगा, जहां सिलेबस पहले से ही बांटा हुआ है। काउंसिल ने सर्कुलर में

कहा-असरदार भाषा टीचिंग स्टूडेंट्स की काबिलियत और सीखने के तरीकों से चलनी चाहिए, न कि सिर्फ टेक्स्टबुक में दिए गए कंटेंट को पूरा करने पर फोकस करना चाहिए। काउंसिल ने स्कूलों से सभी संबंधित टीचर्स और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहा है और उम्मीद है कि वे नए सीखने के तरीके तलाशेंगे, जिससे भारतीय भाषाओं की पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी फिर से जगेगी।

कई स्कूलों में, टीचर्स क्लास 9 और 11 में पूरा सिलेबस पूरा कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स क्लास 10 या 12 में रिवीजन करते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए रिपिटिबल और बोरिंग हो जाता है। नेशनल इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल मौसमी साहा ने कहा-इस बंटवारे का मतलब होगा कि स्टूडेंट्स को बोर्ड एजाम के लिए कम टेस्ट पढ़ने होंगे। प्रिंसिपल को लगता है कि बंटवारे से आईएससी में ज्यादा स्टूडेंट्स इस भाषा को चुनेंगे। जूलियन डे स्कूल के एजुकेशन और डेवलपमेंट डायरेक्टर टेरेंस जॉन ने कहा-क्लास 11 में स्टूडेंट्स में इंडियन लैंग्वेज के बजाय फिजिकल एजुकेशन चुनने का ट्रेंड बढ़ रहा है। बंटवारा उन्हें लैंग्वेज की पढ़ाई की ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा।

सीयू की फर्स्ट सेमेस्टर की अंडरग्रेजुएट परीक्षा 11 मई से

निज संवाददाता : कलकत्ता विश्वविद्यालय (सीयू) ने पहले सेमेस्टर की अंडरग्रेजुएट थ्योरी परीक्षाओं के लिए एक बदलाव हुआ शेड्यूल घोषित किया है, जिन्हें पहले विधानसभा चुनाव की वजह से टाल दिया गया था। ये परीक्षाएं 11 मई से 18 मई तक होंगी। पहले, ये 14 से 27 अप्रैल तक तय थीं। सीयू के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब कई कॉलेज कैंपस पर कब्जा किए हुए सिक्वोरिटी फोर्स 11 मई तक उन्हें खाली कर देंगे। अधिकारी ने कहा-काउंटिंग खत्म होने के बाद, कॉलेजों को अपने कैंपस की सफाई के लिए कुछ दिनों की जरूरत है। क्लासरूम को फिर से व्यवस्थित करना होगा। जब तक परीक्षाएं नहीं हो जाती, दूसरे सेमेस्टर की क्लास शुरू नहीं हो सकती। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जयंत सिन्हा के साइन किए हुए एक नोटिस में कहा गया है-कैंडिडेट बदले हुए थ्योरिटिकल प्रोग्राम के अनुसार उन एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा में शामिल होंगे जो कॉलेज ने पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं और परीक्षार्थियों को जारी कर दिए हैं। बदला हुआ शेड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

माता-पिता जान सकेंगे एआई चैटबॉट से क्या बात कर रहे बच्चे

निज संवाददाता : मेटा ने एक ऐसा टूल लॉन्च किया है, जिससे माता-पिता यह देख सकेंगे कि उनके बच्चे मेटा के एआई चैटबॉट्स से क्या बात कर रहे हैं। हालांकि, अगर बच्चे चैटबॉट से आत्महत्या जैसे विषयों पर बात करते हैं तो माता-पिता को पहले ही अलर्ट मिल जाते हैं, लेकिन यह नया टूल उन्हें बच्चों की एआई चैटबॉट्स के साथ हुई बातचीत के बारे में काफी जानकारी देगा। इसके लिए एक नया इनसाइट्स टैब लाया गया है। इसमें उन्हें सारी जानकारी मिलेगी। फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर निगरानी (सुपरविजन) टूल का उपयोग करने वाले माता-पिता को एक नया "इनसाइट्स" टैब मिलेगा। इस टैब में एक आंशक मिलेगा, जो बच्चे और चैटबॉट के बीच हुई बातचीत को दिखाएगा। इस सेक्शन में उन टॉपिक्स की लिस्ट होगी, जिनके बारे में पिछले सात दिनों में बच्चों ने मेटा के चैटबॉट्स के साथ बातचीत की होगी। कंपनी ने बताया कि कई टॉपिक व्यापक

मेटा ने पेश किया नया टूल



कैटेगरी में आते हैं। इनमें स्कूल, ट्रेवल, लेखन, मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे विषय शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनसाइट्स टैब का उपयोग करने के लिए माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे मेटा के प्लेटफॉर्म पर उन अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल, यह नया टूल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील में माता-पिता के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि वह आने वाले हफ्तों में इस टूल को ग्लोबल लेवल पर भी रोल आउट किया जाएगा। दरअसल, यह नया टूल उस मुकदमे के बाद लाया है, जिसमें मेटा को अपने ऐस पर बाल शोषण को रोकने में विफल रहने के लिए 375 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। मेटा ने एआई वेलबीइंग एक्सपर्ट काउंसिल के गठन की भी घोषणा की है। इस कंपनी "विशेषज्ञों का एक ग्रुप" बताती है।

पाताललोक में बनी बारूदी सुरंगों में भी

दुश्मन की कब्र खोदेगा नया हथियार

भारतीय सेना की माइनफील्ड को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी

निज संवाददाता : भारतीय सेना की माइनफील्ड (सुरंग भेदने की क्षमता) में जबरदस्त इजाफा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने टी-72 और टी-90 युद्ध टैंकों से जुड़े एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी है। मंत्रालय ने हाल ही में सेना के टी-72 और टी-90 टैंकों के ट्रॉल असेंबली की खरीद के लिए लगभग 975 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ट्रॉल असेंबली युद्ध के दौरान बारूदी सुरंगों (माइनफील्ड) को पार करने की सेना की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाएगी। दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ टी-72/टी-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद के वास्ते करीब 975 करोड़ रुपये की लागत से समझौते किए हैं।



* ट्रॉल असेंबली एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है।
* यह खास उपकरण टैंकों के आगे लगाया जाता है।
* इसका काम माइनफील्ड में सुरक्षित रास्ता बनाना होता है।
* विशेष रूप से यह एंटी-टैंक माइन, जिनमें प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज लगे होते हैं, उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण की मदद से बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्रों में सुरक्षित रास्ते बनाए जा सकेंगे, खासकर

उन सुरंगों में जिनमें एंटी-टैंक माइन और मैग्नेटिक फ्यूज लगे होते हैं। इससे भारतीय सेना की आंफेशनल क्षमता और मजबूत

होगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे युद्ध के दौरान टैंकों और अन्य सैन्य वाहनों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार किया जा

शहरी विकास को नई दिशा देने की पहल

निज संवाददाता : भारत में शहरी विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) की शुरुआत की है। करीब 1 लाख करोड़ रुपये के इस महत्वाकांक्षी फंड का लक्ष्य देश के शहरों को वैश्विक स्तर के आर्थिक इंजन में बदलना है। हालांकि, इस योजना की असली परीक्षा राज्यों और शहरी निकायों (यूएलबीएस) के हाथों में होगी, क्योंकि इसके क्रियान्वयन और निवेश जुटाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यूसीएफ की अवधि 2025-26 से 2030-31 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना केवल सरकारी फंडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर, निवेश योग्य और प्रतिस्पर्धी बनाना है। योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण (2025-27) में बुनियादी ढांचे की तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकारें परियोजनाओं की पहचान करेंगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेंगी। इससे शहरों की क्रेडिट रेटिंग और वित्तीय मजबूती बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने शुरू किया अर्बन चैलेंज फंड



दूसरा चरण 2027 से 2029 तक चलेगा, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश और परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा। इस चरण में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी), बॉन्ड और बैंक लोन (पीपीपी) मॉडल की बड़ी भूमिका होगी। सभी राज्यों पर जोर दिया जाएगा। शहरी परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, पुराने शहरों का पुनर्विकास और जलवायु-लचीले (क्लाइमेट-रेजिलिएंट) इंफ्रास्ट्रक्चर इस चरण के प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे। तीसरा और अंतिम चरण 2029 से 2031 तक चलेगा, जिसमें इन परियोजनाओं के परिणाम सामने आएंगे और सफल मॉडलों का विस्तार अन्य शहरों में किया जाएगा। इस चरण का उद्देश्य शहरों को मजबूत आर्थिक प्रोथ हब के रूप में विकसित करना है। योजना की एक अहम शर्त यह है कि केंद्र सरकार कुल फंड का केवल 25 फीसदी ही देगी, जबकि 50 फीसदी से अधिक निवेश बाजार से जुटाना होगा। इसमें बॉन्ड, बैंकिंग सिस्टम और पीपीपी मॉडल की बड़ी भूमिका होगी। सभी राज्यों को इस योजना के तहत समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता जतानी है। विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों को क्रेडिट गारंटी के माध्यम से वित्तीय बाजार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह योजना पारंपरिक सरकारी फंडिंग मॉडल से हटकर बाजार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जो आने वाले वर्षों में भारत के शहरी ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है।



अनुक्रमिका -- 1

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 समग्र जानकारी ('गंभीर समाचार' टीम)

पश्चिम बंगाल में होने वाले आसन्न विधानसभा चुनाव 2026 भारत के महत्वपूर्ण राज्य चुनावों में से एक है। इसकी समग्र, अद्यतन और बिंदुवार विस्तृत जानकारी:

1. चुनाव का परिचय

* यह चुनाव राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए आयोजित किया जा रहा है
* बहुमत के लिए 148 सीटें आवश्यक हैं
* वर्तमान में सरकार सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में है

2. चुनाव कार्यक्रम (Schedule)

* मतदान दो चरणों में कराये गए:
23 अप्रैल 2026 (गुरुवार)
29 अप्रैल 2026 (बुधवार)
* मतगणना (Result): 4 मई 2026
* पूरी प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होगी

3. कुल मतदाता (Voters)

* लगभग 6.7 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के पात्र हैं
* पुरुष, महिला और तृतीय लिंग मतदाता शामिल
* हाल में मतदाता सूची संशोधन (SIR) के कारण लाखों नाम हटाए गए

4. प्रमुख राजनीतिक दल और नेतृत्व

* All India Trinamool Congress (TMC) सत्तारूढ़ दल
* Bhartiya Janta Party (BJP) मुख्य विपक्ष
* अन्य दल: कांग्रेस, वाम दल, क्षेत्रीय गठबंधन
* प्रमुख नेता:
सुश्री ममता बनर्जी (TMC)
श्री सुवेन्दु अधिकारी (BJP)

5. पिछले चुनाव (2021) का संदर्भ

* ने 215 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी
* मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी

6. चुनावी प्रक्रिया

* नामांकन → जांच → प्रचार → मतदान → मतगणना
* मतदान EVM और VVPAT से होगा
* चुनाव का संचालन Election Commission Of India द्वारा किया जाता है

7. इस चुनाव की प्रमुख विशेषताएं

(A) दो-चरणीय चुनाव
* राज्य को दो भागों में बाँटकर मतदान
(B) टेक्नोलॉजी का उपयोग
* AI आधारित निगरानी से Booth Jamming और गड़बड़ी पर नजर
(C) बड़े पैमाने पर मतदाता सूची संशोधन
* लाखों नाम हटाने से चुनावी बहस तेज

8. प्रमुख चुनावी मुद्दे (Key Issues)

* कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा
* बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य
* भ्रष्टाचार और पारदर्शिता
* मतदाता सूची (SIR) विवाद
* शहरी परिवहन और प्रदूषण

9. वर्तमान राजनीतिक माहौल

* TMC vs BJP के बीच सीधा मुकाबला
* आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक विवाद (जैसे कथित डील आदि)
* चुनावी प्रचार में तीव्र प्रतिस्पर्धा

10. सुरक्षा और पारदर्शिता

* संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था
* वेबकास्टिंग और AI निगरानी
* पुनर्मतदान की व्यवस्था (जरूरत पड़ने पर)

11. सरकार गठन की प्रक्रिया

* बहुमत पाने वाली पार्टी सरकार बनाएगी
* राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा
* मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शासन चलाएंगे

12. इस चुनाव का महत्व

* यह चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा
* आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नीतियों पर प्रभाव
* राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर

ध्यान दें :

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य, विकास और शासन मॉडल का निर्णायक मोड़ है। जागरूक मतदाता यदि सही मुद्दों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, तो यह लोकतंत्र को और मजबूत बना सकता है।

.....

अनुक्रमिका -- 2

मतदान से पहले चिंतन

पश्चिम बंगाल में होने वाले आसन्न विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक जागरूक मतदाता के लिए केवल प्रचार नहीं, बल्कि वास्तविक मुद्दों पर गहराई से चिंतन आवश्यक है। नीचे प्रमुख चुनावी मुद्दों को विश्लेषणात्मक और चिंतन योग्य बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है:

प्रमुख चुनावी मुद्दे - मतदाता के लिए चिंतन विषय

1. कानून व्यवस्था और सुरक्षा

* क्या राज्य में आम नागरिक सुरक्षित महसूस करता है?
* राजनीतिक हिंसा और अपराध की घटनाओं पर सरकार का नियंत्रण कितना प्रभावी है?

2. रोजगार और युवाओं का भविष्य

* क्या युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं?
* क्या उद्योग, स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है?

3. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता

* क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है?
* क्या घोटालों और भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई होती है?

4. शिक्षा व्यवस्था

* सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता कैसी है?
* क्या शिक्षा प्रणाली रोजगारोन्मुख (Job-Oriented) है?

5. स्वास्थ्य सेवाएं

* अस्पतालों, डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता कितनी बेहतर है?
* क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं?

6. बुनियादी ढांचा (Infrastructure)

* सड़क, बिजली, पानी और परिवहन की स्थिति कैसी है?
* क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास हुआ है?

7. महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण

* क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण है?
* क्या उन्हें शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिल रहे हैं?

8. सामाजिक समरसता और शांति

* क्या समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बना हुआ है?
* क्या किसी प्रकार का साम्प्रदायिक या सामाजिक तनाव है?

9. महंगाई और जीवन स्तर

* क्या रोजमर्रा की वस्तुएं आम आदमी की पहुंच में हैं?
* क्या आय और खर्च के बीच संतुलन बना हुआ है?

10. पर्यावरण और प्रदूषण

* वायु, जल और कचरा प्रबंधन की स्थिति कैसी है?
* क्या सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है?

11. कृषि और किसान हित

* क्या किसानों को उचित मूल्य और सहायता मिल रही है?
* क्या सिंचाई, बीज और बाजार की व्यवस्था मजबूत है?

12. प्रशासनिक जवाबदेही

* क्या सरकारी अधिकारी और तंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी हैं?
* क्या शिकायतों का समय पर समाधान होता है?

13. प्रवासन (Migration)

* क्या लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ने को मजबूर हैं?
* इसके पीछे के कारण क्या हैं?

14. डिजिटल और तकनीकी विकास

* क्या राज्य डिजिटल सेवाओं और तकनीकी विकास में आगे बढ़ रहा है?
* क्या इससे आम जनता को सुविधा मिल रही है?

15. चुनावी वादे बनाम वास्तविकता

* क्या पिछले वादे पूरे हुए हैं?
* क्या नए वादे व्यवहारिक और संभव हैं?

ध्यान दें :

मतदाता के लिए संदेश
* भावनाओं, प्रचार या प्रलोभनों से ऊपर उठकर सोचें
* मुद्दों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें
* अपने वोट का उपयोग राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर करें

.....

अनुक्रमिका -- 3

पश्चिम बंगाल में उग्र रूप से उभरे प्रमुख मुद्दे

पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी घटनाएं और मुद्दे सामने आए हैं, जिन्होंने जनता और मतदाताओं में व्यापक आक्रोश (Public Anger) पैदा किया। इन्हें प्रमाणिक समाचार और घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित बिंदुवार विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है :

1. शिक्षक भर्ती घोटाळा (SSC Scam) - सबसे बड़ा जनआक्रोश

स्थिति :
* हजारों शिक्षकों की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार के आरोप
* सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25,000+ नियुक्तियां रद्द
* नकली नियुक्ति पत्र, OMR में छेड़छाड़, रिश्वत जैसे आरोप

जन आक्रोश क्यों?

* योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए
* हजारों परिवार आर्थिक संकट में
* लंबे समय तक सड़क पर आंदोलन और प्रदर्शन
ध्यान दें : 2025 में शिक्षकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, कई घायल

2. भर्ती और नौकरी में भ्रष्टाचार (Jobs-for-Cash Scandals)

स्थिति :
* नगर निकाय और अन्य सरकारी नौकरियों में चैसे लेकर नौकरी देने के आरोप
* कई नेताओं से पूछताछ और जांच एजेंसियों की कार्रवाई

जन आक्रोश क्यों?

* युवाओं में यह धारणा बनी कि "मेहनत से नहीं, पैसे से नौकरी मिलती है"
* सिस्टम पर विश्वास कमजोर हुआ

3. महिला सुरक्षा और चर्चित अपराध

स्थिति :
* 2024 में कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या ने देशभर में आक्रोश फैलाया
* इस मामले के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन
ध्यान दें : प्रदर्शनकारियों ने सड़क और रेलवे तक जाम कर दिया

जन आक्रोश क्यों?

* महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल
* प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर असंतोष

4. सामाजिक/सांप्रदायिक हिंसा (Murshidabad Violence 2025)

स्थिति :
* 2025 में मुर्शिदाबाद में हिंसक दंगे
* 3 मौतें, 300+ गिरफ्तार, घरों में आगजनी, पलायन की स्थिति

जन आक्रोश क्यों?

* कानून-व्यवस्था पर सवाल
* सामाजिक असुरक्षा की भावना



विशेष

वैध मतदाताओं को जानकारी और सूचना का अधिकार :

पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा पिछली सरकार के निर्वाचित विधायकों पर राज्य सरकार का खर्च

पश्चिम बंगाल में विधान सभा सदस्य (Member Of Legislative Assembly)/ विधायक (MLA) पर होने वाले वास्तविक आर्थिक खर्च का डाटा आधारित विश्लेषण

यहां पश्चिम बंगाल (West Bengal) पर होने वाले "वास्तविक (Exact/Realistic) आर्थिक खर्च" का डेटा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत है (2023-2025 के अपडेटेड स्रोतों के आधार पर) : पश्चिम बंगाल विधायक (MLA) - वास्तविक आर्थिक खर्च (Exact Analysis)

1. मासिक वेतन (Salary Structure)

* बेसिक वेतन: ₹50,000 प्रति माह
* कुल (भत्तों सहित) :
ध्यान दें : लगभग ₹1.2 लाख ₹1.5 लाख प्रति माह
इसमें शामिल :
* भत्ता (Allowances)
* दैनिक भत्ता (₹2000 प्रति दिन)

2. वार्षिक वेतन + भत्ते खर्च

* ₹1.2 लाख × 12 माह = ₹14.4 लाख/वर्ष
* ₹1.5 लाख × 12 माह = ₹18 लाख/वर्ष
औसत :
₹15 - ₹18 लाख प्रति MLA प्रति वर्ष

3. अतिरिक्त सुविधाएं (Indirect Cost)

(A) आवास + मेंटेनेंस
* सरकारी आवास /

अनुमान: ₹5 - ₹10 लाख/वर्ष

(B) यात्रा + वाहन

* रेल/हवाई यात्रा + वाहन + ईंधन
अनुमान : ₹3 - ₹8 लाख/वर्ष

(C) चिकित्सा

* MLA + परिवार
अनुमान : ₹1 - ₹3 लाख/वर्ष

4. सुरक्षा खर्च (Security Cost)

* सामान्य MLA : लोकल पुलिस
* VIP MLA : PSO/ गार्ड
अनुमान :
₹5 - ₹20 लाख प्रति वर्ष (प्रोफाइल पर निर्भर)

5. MLA Local Area Development Fund (MLA Fund)

* पश्चिम बंगाल में औसतन :
₹2 करोड़ प्रति MLA प्रति वर्ष (राज्य औसत)

ध्यान दें : यह व्यक्तिगत आय नहीं है,

लेकिन सरकार का सीधा खर्च है.

6. पेंशन (Post Retirement Cost)

* एक कार्यकाल (5 वर्ष) के बाद :
लगभग ₹30,000 - ₹50,000 प्रति माह

वार्षिक :

₹3.5 - ₹6 लाख प्रति वर्ष

7. कुल वार्षिक खर्च (Per MLA-West Bengal)

खर्च का प्रकार : वेतन + भत्ते
वार्षिक खर्च : ₹15 - ₹18 लाख

खर्च का प्रकार : आवास + सुविधा

वार्षिक खर्च : ₹5 - ₹10 लाख

खर्च का प्रकार : यात्रा + चिकित्सा

वार्षिक खर्च : ₹4 - ₹10 लाख

खर्च का प्रकार : सुरक्षा

वार्षिक खर्च ₹5 - ₹20 लाख

खर्च का प्रकार : कुल (व्यक्तिगत MLA)

वार्षिक खर्च : ₹30 - ₹60 लाख

खर्च का प्रकार : MLA Fund

वार्षिक खर्च : ₹2 करोड़

8. पश्चिम बंगाल - कुल राज्य खर्च (294 MLA)

* सामान्य MLA खर्च
* ₹30 लाख × 294 MLA = ₹88 करोड़/वर्ष
* ₹60 लाख × 294 MLA = ₹176 करोड़/वर्ष

(B) MLA Fund सहित

* ₹2 करोड़ × 294 MLA = ₹588 करोड़/वर्ष

कुल अनुमानित सरकारी खर्च :

₹700 करोड़ - ₹800+ करोड़ प्रति वर्ष

9. मुख्य निष्कर्ष (Key Reality)

सबसे बड़े खर्च :
* MLA Fund (₹2 करोड़ प्रति)
* सुरक्षा (VIP मामलों में)
वास्तविक सच्चाई :
* पश्चिम बंगाल MLA का वेतन भारत में कम श्रेणी में आता है
* लेकिन कुल खर्च (Fund+ Security+ Perks) मिलाकर एक MLA पर ₹2.5 करोड़ तक का आर्थिक प्रभाव

ध्यान दें :

एक पश्चिम बंगाल MLA पर सरकार का कुल खर्च :
₹2.3 करोड़ - ₹2.6 करोड़ प्रति वर्ष (औसत)
जिसमें :
* वेतन = छोटा हिस्सा
* विकास निधि + सुरक्षा = बड़ा हिस्सा



5. शिक्षक आंदोलन और पुलिस टकराव

स्थिति :
* हजारों "अप्रभावित (Untainted)" शिक्षकों ने नौकरी बचाने के लिए आंदोलन
* सरकारी दफ्तर (विकास भवन) का घेराव, पुलिस से टकराव

जन आक्रोश क्यों?

* निर्दोष लोगों की नौकरी जाने का आरोप
* पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी

6. स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती विवाद

स्थिति :
* मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया पर भी पारदर्शिता पर सवाल
* "Tainted" पैनल पर विरोध और प्रदर्शन

जन आक्रोश क्यों?

* डॉक्टर और छात्रों में असंतोष
* स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न

7. राजनीतिक हिंसा और टकराव

स्थिति :
* चुनावों और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक

झड़पें और हिंसा

* विभिन्न दलों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप

जन आक्रोश क्यों?

* लोकतांत्रिक माहौल प्रभावित
* आम नागरिक के लिए असुरक्षा

8. बेरोजगारी और पलायन

स्थिति :
* उद्योगों की कमी और सीमित नौकरी अवसर
* बड़ी संख्या में युवा अन्य राज्यों की ओर पलायन

ध्यान दें : राजनीतिक स्तर पर भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया

जन आक्रोश क्यों?

* "रोजगार नहीं, पलायन" की स्थिति
* युवाओं में निराशा

9. प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल

स्थिति :
* कई भर्ती और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनियमितता के आरोप
* न्यायालयों और जांच एजेंसियों का हस्तक्षेप

जन आक्रोश क्यों?

* सिस्टम पर भरोसा कमजोर
* "न्याय मिलने में देरी"

समग्र विश्लेषण (Overall Pattern)

इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में जन आक्रोश मुख्यतः इन कारणों से उभरा:

* भ्रष्टाचार (विशेषकर भर्ती घोटाळे)
* रोजगार और युवाओं का भविष्य
* कानून व्यवस्था और सुरक्षा
* महिला सुरक्षा और संवेदनशील अपराध
* राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक विश्वास का संकट

मतदाता के लिए चिंतन

क्या ये समस्याएं स्थायी हैं या अस्थायी? क्या इन पर प्रभावी सुधार हुआ है? कौन-सी नीतियां इन समस्याओं का समाधान दे सकती हैं?

ध्यान दें :

पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में जो मुद्दे उभरे हैं, वे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक असंतोष का संकेत हैं। एक जागरूक मतदाता के रूप में इन तथ्यों और घटनाओं को समझकर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है।

तमिलनाडु में भगवान शिव का 'हीलिंग टेंपल' हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में वैज्ञानिकों

यहां थायराइड जैसी बीमारी से परेशान महिलाएं टेकती हैं माथा

निज संवाददाता : भारत मंदिरों का देश है। यहां देश के विभिन्न राज्यों में प्राचीन और लोकप्रिय कई मंदिर मौजूद हैं। इन्हें में से एक खास शिव मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। भगवान शिव को नैचुरल हीलर (प्राकृतिक उपचारक) के तौर पर भक्त मानते हैं। कई शिव मंदिरों के बारे में यहां मान्यता है कि यहां पर दर्शन करने और प्रसाद लेने से इंसान को कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है, जहां सिर्फ दर्शन और पूजने के लिए नहीं बल्कि अपने थायराइड इश्यू, महिलाएं पीसीओएस की समस्या दूर करने के लिए भी आती हैं। वैसे तो यह मंदिर किसी उपचार का हल नहीं है लेकिन लोगों की श्रद्धा ने उन्हें इस मंदिर की तरफ ले जाती है। तमिलनाडु के छोटे से गांव



थिरुनलकुडी के कुम्बकोणम में बना है नीलकण्ठेश्वर महादेव टेंपल, जो कि तंजावुर जिले में है, जहां सिर्फ दर्शन और पूजने के लिए नहीं बल्कि अपने थायराइड और पीसीओएस जैसी समस्याओं को हील करने के लिए जाते हैं। इस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान शिव की पूजा नीलकण्ठेश्वर के रूप में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवता और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने कंठ में

धारण किया था। जिसकी जलन से भगवान का कंठ नीला हो गया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस मंदिर में माता पार्वती ने भगवान शिव को तेल अर्पित किया था, जिससे उनकी गले की जलन शांत हो सकी। इसी मान्यता के चलते इस मंदिर में भक्तजन थायराइड और पीसीओएस जैसी समस्या को शांत करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्त अपने अंदर के डर, पीसीओएस की

समस्या और थायराइड जैसे गले की प्रॉब्लम की हील करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर की पवित्र और चमत्कारिक विभूति को गले में लगाने से इन सभी समस्याओं से राहत मिलती है। इस मंदिर पर लोगों की गहरी आस्था है। ताकि उन्हें मानसिक रूप से बल मिल सके और वो अपनी बीमारियों से लड़कर उसे ठीक कर सकें। नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर के अलावा कई और भी मंदिर हैं जहां पर भगवान शिव की पूजा वैद्य के रूप में की जाती है। सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है वैद्यस्वर मंदिर। ये मंदिर तंजावुर जिले से दो घंटे की दूरी पर स्थित वैद्यस्वर कोइल मंदिर है। यहां पर सिद्ध कुंड है, जिसे सिद्धासुतम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस जल को भक्त औषधीय मानते हैं जो उनके त्वचा के रोग ठीक हो सके।

पुरी जगन्नाथ मंदिर में लागू होगा सख्त ड्रेस कोड

निज संवाददाता : दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की तर्ज पर अब ओडिशा के विश्वप्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए औपचारिक पोशाक नियम (ड्रेस कोड) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। ओडिशा राज्य विधि आयोग ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजी है कि मंदिर की पवित्रता और हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट ड्रेस कोड को कानूनी रूप दिया जाए। इस सिफारिश में विशेष रूप से महिलाओं के जींस, पैंट या शर्ट पहनकर मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली विधि समिति ने सुझाव दिया है कि श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन कर पोशाक सहिता

की स्पष्ट परिभाषा जोड़ी जानी चाहिए। आयोग के अनुसार, मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं का पहनावा हिंदू संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। प्रस्तावित नियमों के तहत, पुरुष तीर्थयात्रियों के लिए धोती-कुर्ता, पैंट-कमीज, चूड़ीदार-पजामा या कंधे पर गमछा रखना निर्धारित किया गया है। वहीं, 10 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए साड़ी-ब्लाउज या सलवार-कमीज अनिवार्य करने का सुझाव है। 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियां फ्रॉक या गाउन पहन सकेंगी, लेकिन महिलाओं के लिए पश्चिमी परिधानों जैसे जींस और शर्ट पर पूरी तरह रोक की सिफारिश की गई है। हालांकि, मंदिर प्रशासन ने 1 जनवरी 2024 से ही हाफ पैंट, फटी जींस और बिना आस्तीन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की

कोशिश की थी, लेकिन कानूनी प्रावधानों की कमी के कारण इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। शोधकर्ताओं का मानना है कि अधिनियम में संशोधन होने से मंदिर की मर्यादा और आध्यात्मिक वातावरण को बल मिलेगा। पूर्व मंदिर प्रशासक प्रदीप दास के अनुसार, शांति वस्त्र केवल दिखावा नहीं, बल्कि भक्त के भीतर विनम्रता और शांति का भाव जागृत करते हैं, जिससे वे आध्यात्मिक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरी ओर, कुछ विद्वानों का मत है कि इस नियम को बदलते सामाजिक परिवेश और विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को देखते हुए संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाना चाहिए। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी को रोकना नहीं, बल्कि मंदिर की गरिमा बनाए रखना है।

अजब-गजब

544 किलो वजन के साथ बिस्तर से नहीं उठ सकी आठ साल!

निज संवाददाता : दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक बनावट आम लोगों से कुछ अलग है। ऐसी ही अमेरिका की एक महिला थीं जिनका नाम दुनिया की सबसे भारी महिला के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज था। उनका वजन करीब 544 किलो था। यह वजन इतना ज्यादा था कि वह अपने बिस्तर से हिलने-डुलने में असमर्थ थीं। उस महिला ने संघर्ष कर मौत के मुंह से निकलकर खुद को बदलने की ठानी।



दुनिया की सबसे भारी महिला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोसैली ब्रैडफोर्ड नाम की महिला का जन्म पेंसिल्वेनिया (अमेरिका) में हुआ था। बचपन में मां के बिछड़ने और सौतेली मां के साथ खराब रिश्तों के कारण वह तनाव में रहने लगीं। इसी तनाव और अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने भोजन का सहारा लिया। देखते ही देखते उनकी फूड एडिक्शन यानी खाने की लत इतनी बढ़ गई कि कम उम्र में ही उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा। 15 साल की उम्र तक उनका वजन 100 किलो के पार हो चुका था, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। शादी और एक बच्चे की मां बनने के बाद रोसैली का वजन अनियंत्रित हो गया। एक इफेक्शन के कारण उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर

रहना पड़ा, जिसके बाद वजन बढ़ने की रफ्तार और तेज हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन 544 किलो तक पहुंच गया था। उन्हें दुनिया की सबसे भारी महिला के रूप में दर्ज करने के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें नहलाने के लिए भी कई लोगों की मदद लेनी पड़ती थी और वह सालों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाईं। जानकारी के मुताबिक उन्हें नहलाने में करीब 2 घंटे का समय लगता था। इतने भारी वजन के साथ जीना रोसैली के लिए नरक जैसा था। उन्होंने एक समय पर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें असफल रही। इसके बाद उनकी मुलाकात रिचर्ड सिमंस जैसे फिटनेस

विशेषज्ञों से हुई, जिन्होंने उन्हें वजन घटाने के लिए मोटिवेट किया। रोसैली ने हार नहीं मानी और सख्त डाइट और एक्सरसाइज के जरिए करीब 400 किलो से ज्यादा वजन कम किया। यह वजन घटाना भी अपने आप में एक विषय रिकॉर्ड बन गया। आंकड़ों के मुताबिक उनकी यह जर्नी दुनिया भर के मोटे लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। भले ही रोसैली ने भारी वजन कम कर लिया था, लेकिन उनके शरीर पर लटकती अतिरिक्त त्वचा को हटाने के लिए कई सर्जरी की जरूरत थी। साल 2006 में ऐसी ही एक सर्जरी के दौरान पैदा हुई समस्याओं के कारण 63 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई।

करोड़ों साल पुराना फॉसिल 'ऑक्टोपस' नहीं, कठोर खोल वाला समुद्री जीव था

निज संवाददाता : वैज्ञानिकों ने आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों के इस्तेमाल से पाया कि करीब 30 करोड़ साल पुराने एक फॉसिल जीव ऑक्टोपस नहीं बल्कि नाटिलांड था, यानी ऐसा समुद्री जीव जिसके पास कठोर खोल होता है। इस खुलासे ने न सिर्फ एक पुरानी वैज्ञानिक मान्यता को खारिज किया है, बल्कि समुद्री जीवों के विकास से जुड़ी पूरी समझ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह फॉसिल, जिसे पोहलसपिया मेजोनेसिस के नाम से जाना जाता था, साल 2000 में अमेरिका के इलिनोइस राज्य में खोजा गया था। उस समय वैज्ञानिकों को इसमें ऑक्टोपस जैसे कई लक्षण नजर आए थे, जैसे आठ भुजाओं जैसी संरचना, आंखों के निशान और मुलायम शरीर का आकार। इन्हें विशेषताओं के आधार पर इसे प्राचीन ऑक्टोपस मान लिया गया था। हालांकि, अब नई जांच में यह निष्कर्ष पूरी तरह बदल गया है। वैज्ञानिकों ने इस फॉसिल का अध्ययन माइक्रो-सीटी स्कैन और सिंक्रोट्रॉन एक्स-रे जैसी आधुनिक तकनीकों से किया, जिससे पत्थर के



नई शोध में हुआ खुलासा

भीतर छिपी संरचनाओं को बिना नुकसान पहुंचाए देखा जा सका। इसी दौरान उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसे रेडुला कहा जाता है। यह छोटे-छोटे दांतों की एक विशेष संरचना होती है, जो मोलस्क जीवों में पाई जाती है। इस फॉसिल में हर पंक्ति में करीब 11 दांत पाए गए,

जबकि ऑक्टोपस में आमतौर पर 7 या 9 दांत होते हैं। इस अंतर ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह जीव ऑक्टोपस नहीं बल्कि नाटिलांड के ज्यादा करीब था। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस जीव की मृत्यु के बाद उसका शरीर कई हफ्तों तक सड़ता रहा, जिससे उसकी संरचना विकृत हो गई। बाद में जब यह मिट्टी में दबकर फॉसिल बना, तो इसका आकार ऑक्टोपस जैसा दिखाई देने लगा और इसी वजह से शुरुआती वैज्ञानिक इसे सही तरीके से पहचान नहीं सके। आगे की जांच में इस फॉसिल की तुलना एक अन्य ज्ञात नाटिलांड पैलियोकेडमस पोहली से की गई, जिसमें दांतों की संरचना काफी समान पाई गई। इस खोज का सबसे बड़ा असर समुद्री जीवों की विकास समझ पर पड़ा है। पहले माना जाता था कि ऑक्टोपस का विकास बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि उनका विकास बाद में हुआ। प्रमुख वैज्ञानिक थॉमस स्क्रेम्ट्स के मुताबिक, पत्थर में छिपे छोटे-छोटे दांतों ने एक बड़ी वैज्ञानिक गलती को सुधारने का काम किया है।

ने निकाला क्रांतिकारी समाधान

निज संवाददाता : जापान के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के उत्पादन का एक ऐसा तरीका खोज निकाला है, जो इस समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ लोहे के आयरन और अल्ट्रावायलेट (यूवी) रोशनी की मदद से बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस तैयार कर ली है, जिसने पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता खत्म करने की उम्मीद जगा दी है। यह उल्लेखनीय खोज क्यूशू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर ताकाहिरो मात्सुमोतो और उनकी टीम के एक शोध के दौरान हुई। उनका मूल उद्देश्य सस्ते तत्वों से प्रभावी उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) विकसित करना था। इसी प्रक्रिया के तहत एक नियंत्रित प्रयोग में, उन्होंने मेथेनाल, आयरन आयन और सोडियम हाइड्रोजेनसाइड को एक साथ मिलाया। जब इस गोल पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली गई, तो जो परिणाम सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया: इस मिश्रण से बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलने लगी। मात्सुमोतो स्वयं कहते हैं, शुरुआत में तो इस पर यकीन करना ही मुश्किल था। वे इसे एक सुखद इतेफाक बताते हैं जिसने विज्ञान के एक बिल्कुल नए मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। वर्तमान में, अधिकांश हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) से होता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन को मेथेनाल जैसे अल्कोहल से भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत महंगे और दुर्लभ धातुओं वाले उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, लोहा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और अत्यंत सस्ता धातु है। इस नई रिसर्च में लोहे का उपयोग करके उतनी ही रफ्तार से हाइड्रोजन बनाई गई है, जितनी महंगे उत्प्रेरकों से बनती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी हाइड्रोजन उत्पादन दर 9.21 मिलीमोल प्रति घंटा प्रति ग्राम उत्प्रेरक रही, जो अब तक के सबसे बेहतरीन सिस्टम के



बराबर मानी जाती है। इस रिसर्च की सबसे बड़ी खूबी इसकी बहुमुखी प्रतिभा (वर्सैटिलिटी) है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए और पाया कि यह तरीका केवल मेथेनाल तक ही सीमित नहीं है। इससे एथेनाल और प्रोपेनाल जैसे दूसरे अल्कोहल से भी हाइड्रोजन निकाली जा सकती है। इसके अलावा, बायोमास से संबंधित चीजें जैसे ग्लूकोज, स्टार्च और सेल्यूलोज से भी हाइड्रोजन बनाने में सफलता मिली है। हालांकि, अभी ग्लूकोज जैसी चीजों के साथ इसकी दक्षता थोड़ी कम है, लेकिन भविष्य में इसे बेहतर बनाने की पूरी गुंजाइश है। यह तकनीक कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। हालांकि, हर बड़ी खोज के साथ कुछ सवाल भी जुड़े होते हैं। मात्सुमोतो की टीम का कहना है कि वे अभी तक इस पूरी प्रतिक्रिया के सटीक मैकेनिज्म को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, यानी यह प्रक्रिया आंतरिक तौर पर कैसे काम करती है, इसकी बारीकियों का पता लगाना बाकी है। इसके अलावा,

अन्य पदार्थों के साथ इसकी दक्षता को बढ़ाना भी एक चुनौती है। फिर भी, यह तकनीक इतनी सरल है कि इसे कोई भी दोहरा सकता है। प्रोफेसर मात्सुमोतो चाहते हैं कि बच्चे भी इसे ट्राई करें ताकि वे विज्ञान की तरफ आकर्षित हों। भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाइड्रोजन का उपयोग जब ईंधन के तौर पर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, यह सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है। अगर इस नई और सस्ती विधि को बड़े पैमाने पर लागू किया गया, तो हाइड्रोजन से चलने वाली कार और पावर प्लांट्स को चलाना बहुत सस्ता हो जाएगा। लोहे जैसे सस्ते धातु और रोशनी का उपयोग स्थिरता की दिशा में एक मील का पत्थर है। बता दें कि पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की खोज युद्ध स्तर पर जारी है, और हाइड्रोजन को अक्सर भविष्य के सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जाता है। हालांकि, अभी तक हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रियाएं काफी महंगी और जटिल रही हैं, जिससे इसके व्यापक उपयोग में बाधा आ रही है।

स्वास्थ्य

खाद्य खाने के बाद एक गिलास लस्सी पीने से आती है गहरी नींद

निज संवाददाता : लस्सी एक स्वादिष्ट व पौष्टिक पेय माना जाता है। दिन भर धूप में घूमने के बाद एक गिलास लस्सी पीने से जान लौट आती है। फिर, उत्तर भारत समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कई लोग पराठा या रोटी खाने के बाद भी लस्सी पीते हैं। गर्मी के दिन आपने ठंडे पेय से गला तर किया हो या नहीं, थोड़ी देर बाद नींद आ ही जाती है। खट्टा दही अपने आप में एक स्वादिष्ट खाना है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को हेल्दी रखते हैं। हालांकि, सिर्फ खट्टा दही ही नहीं, कुछ लोग चीनी, नमक, नींबू, मसाले मिलाकर लस्सी बनाते हैं, और कुछ राज्यों में तो खट्टे दही को पतला करके उसमें नमक और मसाले मिलाकर पेस्ट बनाकर का रिवाज है। हालांकि, नींद की समस्या तभी होती है जब आप नमक और चीनी के साथ गाढ़ी लस्सी बनाते हैं। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पम्पोनरी डॉक्टर विनी कांतर्क के मुताबिक, लस्सी दूध से बनती है। इसमें ट्रिप्टोफेन होता है, जो सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ाता है। इस हार्मोन का काम नसों को आराम देना है। नतीजतन, लस्सी पीने से कभी-कभी नींद आने लगती है। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अनुभवी न्यूट्रिशनल रूचिका जैन ने एक इंटरव्यू में नींद आने के पीछे का कारण बताया। सबसे पहले, गाढ़ी, मीठी लस्सी में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। एक गिलास लस्सी से पेट भर जाता है। मीठी लस्सी पचाना आसान नहीं होता। खाना पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, जिससे नींद या सुस्ती महसूस होती है। दूसरा, दही में ट्रिप्टोफेन नाम का एक तरह का अमीनो एसिड होता है, जो शरीर में दो ज़रूरी हार्मोन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को रिलीज करने में मदद करता है। मेलाटोनिन नींद में भूमिका निभाता है। क्योंकि दही खाने से दोनो हार्मोन आसानी से रिलीज होते



जायकेदार पेय लस्सी

हैं, इसलिए आलस दब जाता है और नींद आती है। तीसरा, दही में मौजूद ज़िंक और मैग्नीशियम मेलाटोनिन बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। दूध बैक्टीरिया से फ्रैमेंट होकर दही बनता है, जो पेट में फायदेमंद बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। शरीर का ज्यादातर सेरोटोनिन आंतों में बनता है। दही पेट के माहौल को हेल्दी रखकर सेरोटोनिन रिलीज करने में मदद करता है। दिमाग में पीनियल ग्रैंड सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में बदलता है, जो नींद लाने में मदद करता है। गाढ़ी लस्सी अक्सर पचाने में मुश्किल होती है। कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, खासकर अगर उन्हें सीने में जलन की समस्या हो। हालांकि, डॉक्टर हमें याद दिलाते हैं कि लस्सी पीने से ज़रूरी है, यह ज़रूरी है। हालांकि, डॉक्टर हमें याद दिलाते हैं कि लस्सी या दही शरीर को ठंडा रखने के लिए पिया जाता है। कम चीनी वाली पतली लस्सी खाने से गर्मी के दिनों में आराम मिल सकता है। फिर, अगर लस्सी को पूरे खाने के बाद पिया जाए, तो इससे आलस या नींद आ सकती है। यह व्यक्ति की पाचन क्षमता पर भी निर्भर करता है।

ज्यादा दूध की चाय पीने से सेहत को होने वाले पांच खतरे

निज संवाददाता : लोगों को दूध वाली चाय बहुत पसंद है। चाहे गर्मी और उमस भरी सुबह हो या ठंडी शाम, वह परफेक्ट चाय कभी खराब नहीं होती। कोलकाता में, लोगों को एक के बाद एक कप दूध-चा पीते हुए, देखा आम बात है, शायद एक बिस्किट और डेर सारे अड्डे के साथ। हालांकि, इसकी बिना फिल्टर की हुई क्रीमी मिठास के नीचे एक ऐसा मिक्स होता है, जिसे ज्यादा पीने पर शायद उतना नुकसान न पहुंचे जितना लगता है। नारायण हॉस्पिटल की सीनियर डाइटीशियन सतविशा बसु के बताए अनुसार, हर एक कप दूध वाली चाय पीने से सेहत को होने वाले पांच संभावित नुकसान यहां दिए गए हैं, जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।

एसिडिटी और पेट फूलना
चाय की पत्तियों में मौजूद टैनिन (पौधों, छाल, पत्तियों और फलों में पाए जाने वाले नेचुरल कम्पाउंड), जब मिल्क प्रोटीन के साथ मिलते हैं, तो आपके पेट की परत में जलन पैदा कर सकते हैं- खासकर जब इसे खाली पेट पिया जाए, जिससे एसिडिटी, पेट फूलना और आम परेशानी हो सकती है।

आयरन एब्जॉर्शन में कमी
चाय में पॉलीफेनॉल (नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कम्पाउंड) होते हैं जो आयरन के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे इंसान के शरीर के लिए इस ज़रूरी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ, इससे आयरन की कमी हो सकती है, खासकर महिलाओं में।

एक्स्ट्रा चीनी और वजन बढ़ना
दूध वाली चाय में आमतौर पर

एक्स्ट्रा चीनी होती है, और दिन में कई कप पीने से कैलोरी का इनटेक काफी बढ़ सकता है। इससे अपने आप वजन बढ़ सकता है और ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।

कैफ़ीन की लत

नियमित दूध वाली चाय, या ब्लैक टी पीने से, कैफ़ीन पर डिपेंडें हो सकता है, जिससे इनटेक कम करने पर बार-बार सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, नींद में दिक्कत और एंजायटी हो सकती है।

दांतों पर दाग और इनेमल को नुकसान

चाय में मौजूद टैनिन समय के साथ दांतों पर दाग लगा सकते हैं, जबकि चीनी कैविटी और इनेमल के खराब होने का खतरा और बढ़ा देती है, खासकर बार-बार पीने से।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ में निकली 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा'

पैदल मार्च करती नजर आई योगी सरकार



निज संवाददाता : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क पर पिछले दिनों गजब नजारा देखने को मिला जब प्रदेश की योगी सरकार पैदल मार्च करती हुए नजर आई। भारतीय राजनीति में आमतौर पर विरोध का अधिकार विपक्ष के हिस्से में आता है। सरकारें फैसले लेती हैं और विपक्ष सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करता है। लेकिन राजधानी लखनऊ में जो दृश्य देखने को मिला, उसने इस परंपरा को हलट दिया। सत्ता पक्ष खुद सड़क पर उतरा और निशाने पर विपक्ष रहा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर निकली 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ संसद या विधानसभाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों से लेकर गांव-गांव तक राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा। मंगलवार को राजधानी की सड़कों पर उस समय असामान्य हलचल दिखाई दी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हजारों महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते नजर आए। यह पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंची। करीब दो किलोमीटर लंबे इस मार्च में प्रशासनिक अनुमान के मुताबिक 15 हजार से अधिक महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई। तेज धूप और गर्म हवाओं के बावजूद महिलाओं की मौजूदगी ने इसे सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा बड़ा शक्ति प्रदर्शन बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को लेकर बने गतिरोध से जुड़ी है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया संशोधन विधेयक बहुमत के बावजूद आवश्यक दो-तिहाई समर्थन

हासिल नहीं कर सका। उपलब्ध संसदीय आंकड़ों के अनुसार इस विधेयक के पक्ष में लगभग 298 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत पूरा नहीं होने से यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसी घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष ने इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाने की रणनीति अपनाई। लखनऊ में निकली इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मोर्य के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सिर पर गमछा बांधे मुख्यमंत्री का पैदल चलना एक प्रतीकात्मक संदेश की तरह देखा गया। इससे यह संकेत देने की कोशिश रही कि सरकार इस मुद्दे को लेकर केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना चाहती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। पिछले एक दशक में कई राज्यों के चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी गुरुओं के बराबर या कई जगहों पर उससे अधिक रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है और कई विधानसभा क्षेत्रों में उनकी भूमिका निर्णायक साबित होती रही है। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा सीधे तौर पर चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। पदयात्रा के दौरान नेताओं के भाषणों में विपक्षी दलों पर तीखे हमले देखने को मिले। पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ दल बोट बैंक की राजनीति के

कारण महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर पीछे हट गए। उनका कहना था कि राजनीतिक समीकरणों के चलते महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि जो दल महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर विरोध करते हैं, वे आधी आबादी के हितों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। इस पूरे आयोजन का एक अहम पहलू यह भी रहा कि इसे केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस आक्रोश को ब्युत्तर तक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर पर इसी तरह के कार्यक्रमों की शृंखला देखने को मिल सकती है। यह रणनीति सीधे तौर पर संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क दोनों को साधने की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है। महिला आरक्षण को 'आधी आबादी का अधिकार' बनाकर पेश करने की योजना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी मुद्दे को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए उसे भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर स्थापित करना जरूरी होता है। महिला आरक्षण के साथ 'आधी आबादी' का नारा जोड़कर इसे अधिकार और सम्मान के सवाल के रूप में पेश करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस पदयात्रा का एक सामाजिक पक्ष भी है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर लगातार प्रचार किया जाता रहा है। उच्चला योजना, शौचालय निर्माण, मानवत्व सहायता और आवास योजनाओं जैसे कार्यक्रमों का सीधा संबंध महिलाओं से जोड़ा गया है। अब महिला आरक्षण के मुद्दे को इन योजनाओं के साथ जोड़कर एक व्यापक सामाजिक संदेश देने की रणनीति बनती दिख रही है। इससे यह धारणा बनाने की कोशिश है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई स्तरों पर एक साथ काम किया जा रहा है। विपक्ष के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विरोध या समर्थन की राजनीति जनता के बीच सीधी प्रतिक्रिया पैदा करती है। यदि सत्ता पक्ष इसे लगातार जन आंदोलन का रूप देता है, तो विपक्ष को भी अपनी रणनीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और कार्यक्रमों की संख्या बढ़ सकती है। लखनऊ की इस पदयात्रा ने यह भी दिखाया कि राजनीति अब केवल संसद और विधानसभाओं की बहस तक सीमित नहीं रह गई है। अब हर बड़ा मुद्दा सड़क पर उतरकर जनता के बीच ले जाया जा रहा है।

अपनी सरकार की ताकत को मजबूत करने की कवायद में योगी आदित्यनाथ

निज संवाददाता : चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनैतिक हलचल तेज होती जा रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की घड़ी सिर पर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की ताकत को मजबूत करने के लिए कैबिनेट विस्तार की तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस विस्तार का केंद्र बिंदु महिला वोटों को खुश करना हो सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी दलों पर महिला विरोधी होने का ऐसा तंज कसा है कि पूरा माहौल बन गया है। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए योगी सरकार कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर सकती है। न केवल महिलाएं, बल्कि ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटों को भी रखाने के लिए इन वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सियासी समीकरण साधे जा सकते हैं। यह कदम चुनावी साल में सत्ताधारी दल की चतुराई का नमूना पेश करेगा। राज्य की राजनीति हमेशा से जाति, धर्म और लिंग आधारित समीकरणों पर टिकी रही है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर जोर दिया, लेकिन अब चुनावी दबाव में सामाजिक समावेश को प्राथमिकता मिल रही है। वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं की संख्या सीमित है। बेबी रानी माहौर और स्वाति सिंह जैसी कुछ नेता हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगरा की भाजपा सांसद डॉ. प्रेमिला कटियार या गोरखपुर की रवीना कुरेल जैसी सक्रिय महिला नेताओं को जगह मिल सकती है। पश्चिमी इलाके से मेरठ की राजकुमारी दीपा या सहारनपुर की उषा सिद्धू भी दावेदार हो सकती हैं। इनमें से कई विधायक या सांसद हैं, जो जमीनी मुद्दों पर मुखर हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा ने जो प्रचार किया, उसके जवाब में यह कदम महिलाओं को संदेश देगा कि हमारी सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो शोर मचाया, वह अब विधानसभा स्तर पर फल दे सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाए गए महिला विरोधी ठपने ने विपक्ष को रक्षात्मक बना दिया है। योगी सरकार इसी मौके को मुनाने के लिए

कैबिनेट में कम से कम चार-पांच नई महिला मंत्रियों को शामिल कर सकती है। इससे प्रामाण्य महिलाओं से लेकर शहरी मतदाताओं तक संदेश जाएगा कि भाजपा महिलाओं के हितों की रक्षा करेगी। उदाहरण के तौर पर, बुनकर बाहुल्य इलाकों से पिछड़ी जाति की महिलाओं को जगह देकर दोहरी रणनीति अपनाई जा सकती है। अवध क्षेत्र की लक्ष्मी चौधरी या बुटवलखंड की सुनीता सिद्धू जैसी नेता इस फॉर्मूले में फिट बैठती हैं। कैबिनेट विस्तार से न केवल संख्या बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा। यह चुनावी लाभ के साथ-साथ सामाजिक संतुलन भी लाएगा। लेकिन महिला वोटों को खुश करने की रणनीति केवल संख्या पर टिकी नहीं रहेगी। इन महिला मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे, जैसे महिला कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या ग्रामीण विकास। इससे साबित होगा कि यह प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। योगी सरकार पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुहलक्ष्मी योजना और पीक बस जैसी योजनाओं से महिलाओं का विश्वास जीत चुकी है। कैबिनेट विस्तार इन प्रयासों को मजबूती देगा। विपक्षी समाजवादी पार्टी पर पिता-पुत्र की सियासत का आरोप लगाकर भाजपा महिलाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ रही है। अखिलेश यादव सरकार के समय महिलाओं के प्रति उदासीनता के उदाहरणों को बार-बार उछाला जा रहा है। ऐसे में योगी का यह दांव विपक्ष को कटघरे में ला खड़ा करेगा। अब बात ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटों की। उत्तर प्रदेश में ये वर्ग भाजपा की कोर वोट बैंक हैं, लेकिन हालिया लोकसभा परिणामों ने सतर्क कर दिया है। ब्राह्मण समाज में असंतोष की खबरें आ रही हैं। वर्तमान कैबिनेट में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कम है। कैबिनेट विस्तार में प्रयागराज के नंद गोपाल गुप्त नदी या कानपुर के सत्यदेव चोपड़ा जैसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं को जगह देकर इस गैप को भर आ सकता है। ये नेता पार्टी के पुनर्निर्माण में योगी को सहायता दे सकते हैं। ब्राह्मण वोटों को यह संदेश जाएगा कि उनकी उपेक्षा नहीं हो रही। इसी तरह पिछड़ी जाति के लिए निषादा, कुशवाहा और मौर्य समुदायों से प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। आजमगढ़ के शाह आलम या बहराइच के अनिल राजभर जैसे नाम चर्चा में हैं। ये वर्ग भाजपा के लिए गढ़ों में निर्णायक साबित होते हैं।

सही नहीं है सबके सामने बच्चों को डांटना

निज संवाददाता : बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर उन्हें डांटना लगभग हर माता-पिता की आदत होती है। इसमें खुद में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अक्सर हम एक जरूरी बात भूल जाते हैं कि जब हम बच्चे को डांट रहे होते हैं, उस समय आस-पास कौन लोग मौजूद हैं। भीड़-भाड़ वाली जगह, रिश्तेदारों के सामने या स्कूल में डांटना बच्चे के मन पर बुरा असर डाल सकता है। एक पेरेंट के तौर पर आपको उस वक्त शायद कुछ खास फर्क नजर न आए, लेकिन सच यह है कि ऐसी बातें बच्चे के दिल में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। यह छाप धीरे-धीरे उसके आत्मविश्वास और सोच पर असर डालने लगती है। दिल्ली के पीएसआरआई अस्पताल की कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट अर्पिता कोहली के मुताबिक, सबके सामने डांटना सिर्फ उस पल की बात नहीं होती, बल्कि यह बच्चे के कोमल मन पर लंबे समय तक रहने वाले भावनात्मक घाव छोड़ सकता है। जब बच्चे को सबके सामने डांट जाता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी इज्जत दूसरों के सामने कम हो गई है। धीरे-धीरे वह खुद को कम समझने लगता है। उसके अंदर शर्म और डर बैठ जाता है। यही चीज आगे चलकर उसके

पेरेंट्स को बदलनी चाहिए यह आदत



आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और वह हर काम में खुद पर शक करने लगता है। बार-बार पब्लिक में डांट खाने से बच्चा सीखने की बजाय बचने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर गलती बताई तो फिर सबके सामने डांट पड़ेगी। इसलिए वह अपनी गलतियां छिपाने लगता है। इससे वह खुलकर बात करना बंद कर देता है और माता-पिता से दूरी बनाने लगता है। धीरे-धीरे भरोसा भी कम होने लगता है, जो एक अच्छे रिश्ते की सबसे जरूरी चीज है। ऐसे बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाने लगता है। कुछ बच्चे बहुत चुप और डरपोक हो जाते हैं, तो कुछ जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें लोगों के बीच जाने से भी डर लग सकता है। ये बदलाव उनके दोस्ती, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। अगर बच्चे से गलती हो जाए, तो उसे अकेले में प्यार से समझाना ज्यादा असरदार होता है। जब बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तब वह बिना डर के अपनी बात भी कहता है और गलती भी जल्दी समझता है। माता-पिता अगर धैर्य रखें और बच्चों से अच्छे से बात करें, तो रिश्ता मजबूत बनता है। बच्चा भी खुलकर अपने मन की बात बताना है और धीरे-धीरे बेहतर बनता जाता है। बच्चों को सही-गलत सिखाना जरूरी है, लेकिन तरीका उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि कब और कैसे समझाना है, तो हम अपने बच्चे को डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दे सकते हैं। यही छोटी-सी समझ उनके पूरे जीवन को बेहतर बना सकती है।

मनोरंजन

'दम मारो दम' गाने के साथ जीनत ने आशा भोसले को दिया अपनी सफलता का श्रेय

निज संवाददाता : अपनी फिल्म के मशहूर गाने 'दम मारो दम' को लेकर मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प पोस्ट साझा की है। अभिनेत्री ने दिवंगत गायिका आशा भोसले को अपनी सफलता की शुरुआत का श्रेय दिया और गाने से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी बताया, जिसमें संगीतकार आरडी बर्मन ने मूल रूप से तय किए गए ड्रुएट गाने के फैसले को बदल दिया था। जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर दम मारो दम गाने की एक छोटी सी क्लिप साझा की, जिसमें उनका पुराना अंदाज, बेफिक्र स्टाइल और शानदार एक्सप्रेशन आज भी लोगों को लुभाते हैं। वीडियो में उनका किरदार जेनिंस यानी जसवीर एक अलग ही दुनिया में खोई हुई नजर आती है। इस वीडियो को साझा करते हुए जीनत अमान ने कैप्शन में लिखा, काश मैं फिर से 19 साल की हो पाती, जब मैं नई-नई थी, कुछ नया करने की चाहत थी और अपने बड़े मौके के बिल्कुल करीब थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में आगे लिखा, हे भगवान! क्या ये वर्षों का असर है। 'दम मारो दम' की शूटिंग की यादों को मेरे दिमाग में एक धुंधली, लेकिन खूबसूरत याद बना दिया है। मैंने इस गाने की शूटिंग की कहानी पहले भी साझा की है, इसलिए यह पोस्ट आशा



भोसले जी की याद में है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली पोस्ट में बताया था, उन्होंने मुझे मेरी सफलता का संगीत दिया, और इसकी शुरुआत इसी गाने से हुई। जीनत ने कैप्शन में एक और दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 'दम मारो दम' को पहले एक ड्रुएट के रूप में गाने की योजना थी, जिसे आशा जी की बड़ी बहन लता मंगेशकर और दमदार गायिका उषा उल्हास गाने वाली थीं। लेकिन, आरडी बर्मन के इस गाने को लेकर विचार कुछ और ही थे। उन्हें लगा कि इस गाने के लिए आशा जी की खास आवाज ही सबसे सही रहेगी, और

उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। पोस्ट के आखिर में जीनत अमान ने कहा, खैर, मैं इस गाने से जुड़ी अपनी पुरानी पोस्ट को अपनी स्टोरी में साझा कर रही हूँ। फिलहाल आप इस क्लिप का आनंद लें। अगर आपके पास भी 'दम मारो दम' से जुड़ी कोई याद है, तो कमेंट में जरूर साझा करें। मुझे बेहद खुशी होती है, जब मैं आप सभी के अनुभव और मेरी फिल्मों से आपका जुड़ाव पढ़ती हूँ। मुझे पुरा यकीन है कि आप में से सैकड़ों महिलाओं ने किसी न किसी बॉलीवुड थीम पार्टी में जेनिंस/जसवीर की तरह जरूर तैयार होकर हिस्सा लिया होगा।

संभावना सेठ के घर जल्द ही गूंजेगी किलकारी

निज संवाददाता : भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ के घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। शादी के 10 साल बाद वे प्रेरेट हैं। वे सेरेगेसी के जरिए मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस से ये खुशखबरी शेयर की है। लेकिन, क्या आप जानते हैं मां बनने के लिए एक्ट्रेस ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें उन्हें काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा है। क्योंकि, एक्ट्रेस मां बनने के लिए काफी वक्त से ट्राई कर रही थीं। उन्होंने आईवीएफ का सहारा भी लिया। साथ ही मिसकैरेज और कई इंजेक्शंस का दर्द भी झेला था। संभावना सेठ ने अपने एक व्हांग में बताया था कि वो तीन महीने प्रेरेट थीं और 18 दिसंबर 2024 को फैंस के संग ये खुशखबरी शेयर करने वाली थीं। लेकिन ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। संभावना के पति अविनाश मिश्रा ने व्हांग में बताया था-डॉक्टरों ने कहा था जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, सबकुछ अच्छा है, बच्चों की धड़कने भी बढ़ गई है।

सुभाष घई ने किया 'खलनायक रिटर्न्स' का ऐलान

फर्स्ट पार्ट में बल्लू बनकर संजय दत्त ने लूटा था बाक्स ऑफिस

निज संवाददाता : सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म खलनायक बॉलीवुड की सबसे यादगार और बेहतरीन फिल्मों में से एक है। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्राफ जैसे अभिनेताओं से सजी यह फिल्म 6 अगस्त, 1993 को रिलीज हुई थी और इसने बाक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब 33 साल बाद खलनायक के सीकवल खलनायक रिटर्न्स का ऐलान हो गया है। फिल्म से संजय दत्त का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। फिल्म खलनायक के बाक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक नजर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पहले फिल्म खलनायक को अभिताभ बच्चन के साथ बनाया जा रहा था और इसका नाम देवा रखा गया था, लेकिन एंग्री यंग मैन (अभिताभ) और सुभाष घई के बीच फिल्म बनाने के तरीकों को लेकर काफी मतभेद थे, जिसकी वजह से यह फिल्म बंद कर दी



गई। बाद में सुभाष घई ने अपनी इस फिल्म को नए सिरे से बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में बल्लू का किरदार नाना पाटेकर निभाने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर को एहसास हुआ कि उन्हें इस रोल के लिए किसी जोशीले और नौजवान एक्टर की जरूरत है और फिर एंग्री हुई संजय दत्त की। इधर, जैसे ही बल्लू के रोल के लिए सुभाष घई ने संजय दत्त को फाइनल

किया, उधर, अनिल कपूर ने भी इस किरदार को निभाने की इच्छा जताई और सुभाष घई को खूब मनाया, लेकिन उन्होंने संजय दत्त से पहले ही वादा कर दिया था। खलनायक में जैकी श्राफ ने इन्स्पेक्टर राम कुमार सिन्हा की भूमिका निभाई है। पहले ये रोल आमिर खान को ऑफर किया गया था, लेकिन अनिल कपूर की

तरह आमिर भी फिल्म बिल्लू का किरदार निभाना चाहते थे। हालांकि, अप्रैल 1993 में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद ये फिल्म फिर रुक गई। बॉलीवुड गलियारों में चर्चा होने लगी कि ये फिल्म दूसरी बार बंद होने जाएगी। जब मई 1993 में संजय दत्त जेल से बाहर आए तो इस फिल्म पर फिर से काम शुरू हुआ। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, फिल्म खलनायक ने बाक्स ऑफिस पर सिर्फ 20 लाख रुपये की ओपनिंग की थी, लेकिन ये फिल्म सिनेमाघरों में 8 हफ्तों से ज्यादा चली और इसने 12.5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खलनायक केवल 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, जिसने बाक्स ऑफिस पर जबरदस्त 400 फीसदी का मुनाफा कमाया। इसके साथ ही ये आंखें के बाद 1993 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।